नई दिल्ली ■ बुधवार 07 मई 2026 ■ मूल्य 5.00 ■ वर्ष 14 ■ अंक 39 ■ पृष्ठ 08

JBT
जनभावना टाइम्स
www.thejbt.com

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल, करनाल एवं मुजफ्फरनगर से प्रकाशित

04 सियासत का नया व्याकरण लिखता जनादेश 2026 | 07 अहमदाबाद करेगा IPL फाइनल की मेजबानी | तारा सुतारिया और आदित्य रॉय चर्चा में 08

भारत-वियतनाम साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, साथ जीतेंगे : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत और वियतनाम के संबंध अब बेहतर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं और दोनों देश मिलकर विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, और साथ जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच बुधवार को हुई उच्चस्तरीय वार्ता के बाद भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों को बेहतर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा की। दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, कनेक्टिविटी और रणनीतिक सहयोग को नई गति देने का संकल्प संकल्प भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि राष्ट्रपति तो लाम का भारत दौरा दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों और आपसी प्राथमिकता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि यह साझेदारी अब और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-वियतनाम के बीच व्यापार पिछले दशक में दोगुना होकर 16 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अब दोनों देशों ने इसे 2030 तक 25 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। दवाओं, कृषि, मत्स्य और पशु उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर सहमति बनी है। बहुत जल्द, वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का और हम वियतनाम के डूरियन और पोमेलो का स्वाद लेंगे। दोनों देशों ने वित्तीय सहयोग बढ़ाने के तहत भारत के यूपीआई और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर सहमति जताई। साथ ही एयर कनेक्टिविटी, स्टेट-टू-स्टेट और सिटी-टू- सिटी सहयोग को भी बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है। दोनों देशों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया।

वियतनाम के सहयोग से भारत, आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध हैं।

चम्पा सभ्यता के मंदिरों के संरक्षण और प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण जैसे कदम इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत और वियतनाम तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और नई रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से दोनों देश एक-दूसरे के विकास में सहायक बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अंत में बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि एक-दूसरे के विकास में सहयोग करना ही दोनों देशों की साझा प्रगति का मार्ग है।

जालंधर BSF कैंप व अमृतसर बम धमाके में पाकिस्तान का हाथ : DGP

चण्डीगढ़। पंजाब में मंगलवार रात 3 घंटे के भीतर 2 जगह ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट रात करीब 8 बजे जालंधर में बीएसएफ के पंजाब हेडक्वार्टर के बाहर हुआ। यह धमाका कूरियर बॉय की एक्टिवा में हुआ। दूसरा ब्लास्ट रात करीब 11 बजे अमृतसर में आर्मी कैंप के बाहर हुआ। यहां कैंप के भीतर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश थी लेकिन वह दीवार से टकराकर फट गया।

बुधवार सुबह डीजीपी गौरव यादव पहले अमृतसर और फिर जालंधर में ब्लास्ट वाली साइट पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये दोनों आईईडी ब्लास्ट हो सकते हैं। यह संभावना है कि इन्हें टाइमर या रिमोट से ब्लास्ट किया गया है। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। धमाके की टाइमिंग को लेकर उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी की वजह से कराए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री आनंदपुर साहिब में कहा कि ये ब्लास्ट बीजेपी के पंजाब इलेक्शन की तैयारी है। भाजपा छोटे-मोटे ब्लास्ट करवाकर लोगों को डराकर वोट लेना चाहती है। यह भाजपा का स्टाइल है। चुनाव वाले स्टेट में ब्लास्ट और दंगे करवा दो। ब्लास्ट के बाद सीएम मान ने बुधवार को अपना जालंधर दौरा टाल दिया।

सीएम के भाजपा पर आरोपों को लेकर पंजाब से दिल्ली तक बवाल मच गया। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने सीएम को चैलेंज किया कि उन पर एफआईआर दर्ज करके दिखाएं। आप छोड़ने वाले सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सीएम पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर आईएसआई की गोद में बैठ रहे हैं। उन्हें खराब लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए।

जालंधर ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने रिटायर्ड बीएसएफ जवान के बेटे को हिरासत में लिया है। मामले की जांच के लिए एनआईए की टीमें भी पहुंच गई हैं। वहीं बुधवार सुबह खालिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से एक पोस्टर शेयर कर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली गई। जिसमें कहा गया कि उनके टारगेट पर अमृतसर रेंज के डीआईजी संदीप गोयल व उनका पूरा परिवार है। हम इतना खून बहाएंगे कि सब कुछ लाल दिखाई देगा।

संक्षिप्त खबरें

शशि शेखर वेम्पति बने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शशि शेखर वेम्पति को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक शशि शेखर वेम्पति तीन साल की अवधि के लिए इस पद पर कार्यभार संभालेंगे। यह नियुक्ति प्रसून जोशी के पद छोड़ने के बाद की गई है। प्रसून जोशी को हाल ही में प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया है, जिसके चलते उन्होंने सीबीएफसी प्रमुख का पद छोड़ा। शशि शेखर वेम्पति मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लंबे अनुभव रखते हैं। इससे पहले वे प्रसार भारती के सीईओ भी रह चुके हैं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को आमतौर पर सेंसर बोर्ड के रूप में जाना जाता है, जो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक संस्था है। यह चलचित्र अधिनियम 1952 के तहत फिल्मों, विज्ञापनों और टीवी सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रमाणित करता है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बाद हिंसा पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

कोलकाता। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हो रही हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता के न्यूटाउन इलाके में मंगलवार को मधु मंडल नाम के भाजपा कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य के विभिन्न इलाकों से हिंसा और तोड़फोड़ की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसको देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस के पुलिस आयुक्त तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य पुलिस अधिकारियों को लगातार गश्त करने और स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव बाद होने वाली किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने के दो दिन बाद बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री के इस्तीफा के बाद राज्य में नई सरकार के गठन के लिए आगे की कार्रवाई आज से आरंभ हो गयी। उल्लेखनीय है कि, बीते 9 अप्रैल को असम की 126 विधानसभा के लिए मतदान हुआ था। मतों की गिनती बीते 4 मई को हुई थी। जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अकेले 82 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है। बावजूद भाजपा ने इस बार का चुनाव एनडीए के बैनर तले लड़ा था। इस तरह एनडीए के दो अन्य सहयोगी असम गण परिषद (अगप) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) ने भी 10-10 सीटों पर जीत हासिल की है। इस तरह एनडीए गठबंधन को 126 सीटों में से 102 सीटें मिली हैं। वहीं, कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 19 सीटें आई हैं। जबकि, कांग्रेस गठबंधन में शामिल राइजर दल को 2 सीटें, एआईयूडीएफ 2 सीटें और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को एक सीट मिली हैं। वहीं वामपंथी पार्टियों का इस बार पूरी तरह से सफाया हो गया है।

तमिलनाडुः सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने टीवीके को दिया सशर्त समर्थन

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद त्रिशंकु स्थिति बनने पर राज्य में सरकार गठन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने सी. विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) को सशर्त अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। कांग्रेस ने इस गठबंधन में किसी भी सांप्रदायिक ताकत और संविधान में विश्वास न करने वाली ताकत को शामिल नहीं किया जाएगा।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तमिलनाडु प्रभारी गिरिश चोडंकर ने बुधवार को एक बयान जारी कर अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के लोगों, खासकर युवाओं ने एक धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और कल्याणकारी सरकार के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है। इस जनादेश का सम्मान करते हुए टीवीके के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का समर्थन करना संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तमिलनाडु में टीवीके को सरकार बनाने के लिए पूर्ण समर्थन देने का फैसला किया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है–ऐसी

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

PRESS RELEASE

किसी भी सांप्रदायिक ताकत को इस गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा, जो भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखती हो। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन का उद्देश्य के. कामराज के स्वर्णिम शासन को फिर से स्थापित करना, ईवी रामासामी पेरियार के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और डॉ. बीआर आंबेडकर के संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह गठबंधन केवल सरकार गठन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय निकाय, लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौते के रूप में जारी रहेगा।

होर्मुज जलडमरुमध्य दोबारा न खोला गया तो ईरान पर बमबारी होगीः ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरुमध्य नहीं खोलने की स्थिति में ईरान पर और ज्यादा बमबारी करने की बुधवार को चेतावनी दी। इस बीच, युद्ध खत्म करने के लिए दोनों पक्षों के समझौते के करीब पहुंचने की खबर भी सामने आई है।

अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियस की खबर में अमेरिकी अधिकारियों और दो अन्य सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर एक पृष्ठ के सहमति पत्र को मंजूरी देने और विस्तृत परमाणु वार्ताओं के लिए एक रूपरेखा तय करने के करीब पहुंच गए हैं। खबर के अनुसार अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान अगले 48 घंटे के अंदर विभिन्न प्रमुख बिंदुओं पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। हालांकि खबर में यह भी कहा गया है कि अभी कुछ तय नहीं है। खबर में कहा गया है कि युद्ध

शुरू होने के बाद से पहली बार दोनों पक्ष किसी समझौते के इतनी ज्यादा करीब पहुंचे हैं। ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा कि अगर ईरान पहले से तय शर्तों को मान ले तो इस समय जारी बड़ा सैन्य अभियान 'एपिक फ्यूरी' खत्म हो जाएगा। समुद्री नाकाबंदी हट जाएगी और होर्मुज जलडमरुमध्य ईरान समेत सभी के लिए खुल जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने सहमति नहीं जताई, तो बमबारी शुरू होगी। यह बमबारी दुर्भाग्य से पहले की तुलना में बहुत बड़े स्तर पर और बहुत तेज होगी।

एक्सियस की खबर के अनुसार, इस समझौते में ईरान परमाणु संवर्धन को अस्थायी रूप से रोकने पर सहमत होगा, जबकि अमेरिका उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा देगा, साथ ही ईरान के अरबों डॉलर के 'फ्रीज' किए गए धन के इस्तेमाल की अनुमति देगा। खबर के अनुसार दोनों देश होर्मुज जलडमरुमध्य से गुजरने वाले जहाजों और व्यापार पर लगी पाबंदियों को भी कम या खत्म करने पर सहमत हो सकते हैं।

खबर में कहा गया है कि इस सहमति पत्र में बताई कई शर्तें तभी लागू होंगी जब दोनों पक्षों के बीच अंतिम समझौता हो जाएगा। खबर के अनुसार अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर से युद्ध शुरू होने की आशंका बनी रहेगी, या स्थिति लंबे समय तक अनिश्चित बनी रह सकती है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात के बाद चीन ने ईरान युद्ध में समग्र संघर्ष विराम की अपील की। अराघची 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किए जाने के बाद से पहली बार चीन की यात्रा पर हैं।

सबरीमाला मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने 1962 के फैसले को चुनौती देने के तरीके पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर मामले पर सुनवाई के 12वें दिन बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने उस तरीके पर सवाल उठाया, जिसमें सुधारवादियों के एक समूह ने उच्चतम न्यायालय के 1962 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित बहिष्कार की परंपरा को सही ठहराया गया था।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान बेंच ने कहा कि उस फैसले की समीक्षा के लिए पुनर्विचार याचिका या क्यूरेटिव याचिका दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका कानून सम्मत नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि 5 मई को हमने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन से पूछा था कि आपकी याचिका क्यों सुनी जाए। आज हम आपसे भी पूछ रहे हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत ये याचिका क्यों सुनी जाए। आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की ओर से वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन पेश हुए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी सुधारवादियों का एक समूह है और इसमें शामिल एक व्यक्ति के पिता कार्यकर्ता असगर अली इंजीनियर को बोहरा समुदाय से निष्कासित कर दिया गया था। राजू रामचंद्रन ने कहा कि बहिष्कार करना मानव की गरिमा का उल्लंघन है। तब जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि उनके मुवक्किलों ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की थी।

कोर्ट ने कहा कि 1962 के फैसले के विरोध में पुनर्विचार याचिका या क्यूरेटिव याचिका

दाखिल की जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत नहीं। तब रामचंद्रन ने कहा कि उनके मुवक्किलों की ओर से अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका अन्य याचिकाओं की तुलना में कानूनी रूप से ज्यादा सही थी। पांच मई को कोर्ट ने याचिकाकर्ता इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन को फटकार लगाते हुए उसकी 2006 की याचिका को कानून का दुरुपयोग बताया था। कोर्ट ने पूछा था कि आपने यह याचिका क्यों दायर की, क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा था कि कोई भी कानूनी संस्था व्यक्तिगत आस्था का दावा नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा था कि विश्वास व्यक्ति का होता है संस्था का नहीं।

आपके पास कोई अंतरात्मा नहीं है। जस्टिस अरविंद कुमार ने भी इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन से पूछा था कि क्या याचिका दाखिल करने के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया था और क्या संगठन के अध्यक्ष ने इसे मंजूरी दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 28 अप्रैल को कहा था कि किसी धार्मिक संस्था के प्रबंधन के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि उसके संचालन का कोई ढांचा न हो और प्रबंधन को लेकर अराजकता की स्थिति नहीं हो सकती है।

कोर्ट ने कहा था कि ऐसी संस्थाओं के कामकाज की एक व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एजे मसीह, जस्टिस पीबी वराले, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल हैं।

आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन से जुड़े संस्थानों के लिए नए मानक जारी किए

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी मुद्रा लेनदेन से जुड़े संस्थानों के लिए नए मानक जारी करते हुए कहा है कि अब 'मनी चेंजर्स' के लिए नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे।

केंद्रीय बैंक ने 'विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अधिकृत व्यक्ति) विनियमन, 2026' के तहत यह बदलाव किया है। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करना और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। आरबीआई ने बुधवार को कहा कि नए ढांचे के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए सभी संस्थाओं को उसकी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही

विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री के लिए अधिकृत डीलरों की श्रेणियों और नियमों को भी संशोधित किया गया है। नए नियमों के तहत, नए लाइसेंस के लिए आवेदन तीन श्रेणियों में किया जा सकेगा। बैंकों को अधिकृत डीलर श्रेणी-1 के तहत आवेदन करना होगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), पूरी तरह मनी चेंजर का काम करने वाले या दो वर्षों से काम कर रहे एवं दो वित्त वर्षों में औसतन 50 करोड़ रुपये का वार्षिक विदेशी मुद्रा कारोबार करने वाले संस्थान अधिकृत डीलर श्रेणी-2 के तहत आवेदन कर सकेंगे। वहीं, विदेशी मुद्रा से जुड़े नवाचार आधारित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने वाली कुछ अन्य संस्थाओं को अधिकृत डीलर श्रेणी-3 में रखा गया है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि पूरी तरह मनी चेंजर के रूप में काम करने का लाइसेंस पाने के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय उन आवेदनों के जो इन नियमों के लागू होने से पहले प्राप्त हुए हैं। नए नियमों के तहत लाइसेंस पाने के लिए संस्थाओं का कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत होना और निर्धारित न्यूनतम नेटवर्थ मानदंडों को पूरा करना भी जरूरी होगा।

स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च, एक प्लेटफॉर्म से ही निपटेंगे सभी काम

नई दिल्ली। देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को डिजिटल रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया। यह पहल 10वें नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इन्क्लूसिविटी के दौरान किया गया। यह पोर्टल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत विकसित किया गया है और आशा है कि यह मरीजों के हेल्थ डेटा का सुरक्षित आदान-प्रदान सुनिश्चित करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह पोर्टल अलग-अलग स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बिखरे सिस्टम को एक साथ जोड़कर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। अब तक कई ऐप और पोर्टल अलग-अलग काम कर रहे थे, जिससे डेटा दोहराव और समय की बर्बादी हो रही थी। मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ भारत पोर्टल के जरिए एक ही जगह पर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

सभी डेटा एंट्री संभव होगी, कई लॉगिन की जरूरत खत्म होगी और रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग आसान होगी। इसके साथ स्वास्थ्य कर्मियों को राहत आशा, एएनएम, सीएचओ और मेडिकल ऑफिसर्स को अब अलग-अलग सिस्टम पर काम नहीं करना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म से ही सभी काम निपटेंगे, जिससे उनका समय और मेहनत दोनों बचेंगे। मंत्रालय के मुताबिक इससे इंफ्रास्ट्रक्चर लागत में 20–30 प्रतिशत तक कमी, डेटा एंट्री और स्टाफ दोहराव में 20–40 प्रतिशत तक कमी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेज आएगी। मंत्रालय के मुताबिक यह पोर्टल भारत के डिजिटल हेल्थ सिस्टम को एकीकृत करने की दिशा में अहम कदम है, जिससे भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और डेटा आधारित फैसले संभव होंगे।

प्रदूषण विभाग की बैठक में उठी वन टाइम स्कीम की मांग, उद्यमियों को एनओसी लेने के निर्देश

नोएडा। नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन भवन, सेक्टर-6 में मंगलवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी ऋतेश कुमार तिवारी और सहायक पर्यावरण अभियंता किशन सिंह ने उद्यमियों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान को लेकर मार्गदर्शन दिया। बैठक के दौरान उद्यमियों ने प्रदूषण विभाग से संबंधित विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक सुझाव दिए और नियमों के पालन पर जोर दिया।

क्षेत्रीय अधिकारी ऋतेश कुमार तिवारी ने कहा कि सभी उद्यमियों के लिए प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। जिन उद्यमियों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे जल्द आवेदन करें। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और यदि किसी प्रकार की परेशानी आती है तो उद्यमी सीधे विभाग से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विभाग उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव सहयोग करेगा, लेकिन एनओसी लेना जरूरी है।

बैठक में नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने कहा कि कई उद्यमियों ने जानकारी के अभाव या अन्य कारणों से पहले एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया था, लेकिन अब वे आवेदन करना चाहते हैं।

वर्तमान में विभाग द्वारा पुराने वर्षों के लंबित शुल्क और अन्य चार्ज भी वसूले जा रहे हैं। उन्होंने विभाग से अनुरोध किया कि एक बार के लिए विशेष योजना लागू की जाए, जिसके तहत अब तक आवेदन नहीं करने वाले उद्यमियों को बिना किसी पिछली तिथि की पेनाल्टी या अतिरिक्त शुल्क के आवेदन करने का अवसर दिया जाए। विपिन कुमार मल्हन ने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि यदि यह सुविधा दी जाती है तो भविष्य में दोबारा ऐसी मांग नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन इस संबंध में लिखित आश्वासन देने के लिए भी तैयार है।इस पर ऋतेश कुमार तिवारी ने कहा कि यह नीति से जुड़ा विषय है। यदि एसोसिएशन लिखित प्रस्ताव देती है तो उसे उच्च अधिकारियों और लखनऊ मुख्यालय तक पहुंचाकर आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए विभाग उद्यमियों के सहयोग की अपेक्षा करता है। वहीं, विपिन कुमार मल्हन ने भरोसा दिलाया कि उद्यमी विभाग के सुझावों का पूरी तरह पालन करेंगे और शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

बैठक में एनईए की प्रदूषण नियंत्रण समिति के चेयरमैन धर्मवीर शर्मा ने अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उचित मार्गदर्शन दिया। इस दौरान महासचिव वीके सेठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश कोहली, मुकेश कक्कड़, कोषाध्यक्ष एससी जैन, उपाध्यक्ष आरएम जिंदल, सुधीर श्रीवास्तव, प्रभात मेहता, सचिव राहुल नैययर, आलोक गुप्ता, वीरेंद्र नरूला, राजकुमार गुप्ता, सह कोषाध्यक्ष एमपी सिंह, संयुक्त सचिव जीके बंसल, झुमा विश्वास नाग, छाया सिन्हा सहित बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे।

यीडा और जापान के एमईजे के बीच एमओयू, मेडिकल डिवाइस सेक्टर में निवेश व तकनीकी सहयोग को मिलेगा बढ़ावा

ग्रेटर नोएडा। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) और एमईजे के बीच चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, तकनीकी नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करना है।

एमओयू के तहत दोनों पक्ष मेडिकल डिवाइस सेक्टर में अनुसंधान एवं विकास , तकनीकी हस्तांतरण, निवेश प्रोत्साहन और स्टार्टअप सहयोग जैसे क्षेत्रों में मिलकर कार्य करेंगे। यीडा जहां आवश्यक अवसंरचना, भूमि आवंटन, नीतिगत प्रोत्साहन और नियामकीय सहयोग प्रदान करेगा, वहीं एमईजे जापानी तकनीकी विशेषज्ञता, कंपनियों की भागीदारी और ज्ञान हस्तांतरण में सहयोग करेगा। इस समझौते के तहत यीडा मेडिकल डिवाइस पार्क को जापानी कंपनियों के लिए निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही, दोनों पक्ष संयुक्त शोध परियोजनाओं, प्रयोगशालाओं की स्थापना और सेमिनार व व्यापार मिशनों के आयोजन के माध्यम से सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत भारतीय और जापानी कंपनियों के बीच तकनीकी समझौते, गुणवत्ता मानकों का आदान-प्रदान और निर्माण प्रक्रियाओं में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

वहीं, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन, फंडिंग, हैकाथॉन और मेंटरशिप जैसे कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा, जो 30 दिनों के भीतर तैयार होगा और 60 दिनों में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करेगा।

छत से युवक-युवती के कूदने के मामले में पति-पत्नी गिरफ्तार

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर-22 अंतर्गत चौड़ा रघुनाथपुर गांव में युवक-युवती के छत से गिरने के मामले में पुलिस ने मकान मालिक और उसकी पत्नी को बुधवार सुबह गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस घटना में युवक की मौत हो गई थी, जबकि युवती जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है।

थाना सेक्टर 24 के प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया कि गत सोमवार सुबह करीब पांच बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 22 में हनुमान मंदिर के पास एक मकान की चौथी मंजिल से पुनीत (26) तथा कुमारी विद्या दास (20) ने आत्महत्या करने की नीयत से छलांग लगा दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस दोनों को गंभीर हालत में नोएडा के जिला अस्पताल ले गई, लेकिन चिकित्सकों ने पुनीत चौहान को मृत घोषित कर दिया, जबकि विद्या दास की हालत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। कुमार ने बताया कि इस मामले में मृतक के पिता कृष्णपाल ने बुधवार को थाना सेक्टर 24 में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को इस घटना में चौड़ा रघुनाथपुर गांव निवासी हितेश राणा और उसकी पत्नी चंचल राणा की भूमिका संदिग्ध नजर आई।

थाना प्रभारी के अनुसार, पुनीत मेरठ का रहने वाला था और आरोपी चंचल राणा भी मेरठ की रहने वाली है। कॉलेज में पढ़ते समय दोनों की बातचीत थी। कुछ समय पूर्व चंचल राणा के जन्मदिन पर पुनीत ने उसे सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी थी। इस बीच दोनों एक-दूसरे से मिले। उन्होंने कहा कि इसके बाद हितेश राणा को अपनी पत्नी के ऊपर शक हुआ, और उसने पुनीत को बातचीत करने के लिए घटना वाले दिन चौड़ा गांव स्थित अपने घर बुलाया।

थाना प्रभारी के अनुसार, पुनीत अपनी प्रेमिका विद्या के साथ उसके घर पहुंचा। दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। इसके बाद पुनीत और विद्या हितेश राणा के घर पर ही रात के समय रुक गए। अगले दिन सुबह दोनों छत से गिरे मिले। इस घटना में पुनीत की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने हितेश और चंचल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने कहा कि मामले में विस्तृत जांच जारी है।

पड़ोसी ने युवक की गोली मारकर हत्या की, आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के एक गांव में बुधवार तड़के 25 वर्षीय एक युवक की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटों में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसकी पहचान मंगेश (31) के रूप में हुई है।

पुलिस प्रवक्ता विजय कुमार ने बताया कि प्रारंभिक तफ्तीश में पता चला कि गांव निवासी साजन आज तड़के जब एक शादी समारोह से घर लौटा तभी उसके पड़ोसी मंगेश (31) ने उस पर गोलियां चला दीं। साजन को तीन गोलियां लगीं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच, पुलिस को सूचना मिली कि मंगेश और उसका एक साथी कार में सवार होकर फरार होने की फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस दल ने उन्हें घेर लिया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कार से उतरकर भागने की कोशिश के दौरान दोनों ने पुलिस दल पर गोलियां भी चलाईं। जवाबी कार्रवाई में मंगेश पैर में गोली लगने से घायल हो गया और उसे काबू कर लिया गया, हालांकि उसका साथी फरार हो गया। उन्होंने बताया कि घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि उसके पास से पुलिस ने एक अवैध पिस्तौल, दो कारतूस बरामद किए हैं।

उन्होंने कहा, ''प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि साजन और मंगेश के बीच नाली की सफाई व कूड़ा डालने को लेकर विवाद था। संभवतः इसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया।'' उन्होंने बताया कि परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

सड़क हादसे में छह वर्षीय बच्ची की मौत

नोएडा। जेवर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक सड़क हादसे मं छह वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जेवर थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि छह वर्षीय सुहाना सड़क पार कर रही थी कि तभी मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति ने उसे टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि बच्ची से टकराने के बाद बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार अनिल को भी चोट आई। अधिकारी ने बताया कि बच्ची और बाइक सवार को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुहाना की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नोएडा में पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप, मारपीट के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

नोएडा। नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में मामूली पार्किंग विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां कुछ लोगों ने दुकान में घुसकर एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5 मई 2026 को ग्राम वाजिदपुर निवासी पीड़ित ने थाना एक्सप्रेसवे में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में बताया गया कि संजय चौहान, कर्नल चौहान, दीपांशु चौहान, प्रिंश (पुत्र संजय चौहान) और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद पीड़ित की दुकान में घुसकर उसके पिता के साथ मारपीट की। आरोपियों ने न केवल मारपीट की, बल्कि गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की शिकायत के आधार पर थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने मामला दर्ज कर मुकदमा पंजीकृत किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और 6 मई 2026 को कार्रवाई करते हुए ग्राम नंगली वाजिदपुर से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कर्नल (35 वर्ष) पुत्र कालूराम, दीपांशु चौहान (23 वर्ष) पुत्र सुरेंद्र और अक्षित (26 वर्ष) पुत्र गजेंद्र के रूप में हुई है। सभी आरोपी नंगली वाजिदपुर, नोएडा के निवासी हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मामले की विस्तृत जांच जारी है, ताकि सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून को हाथ में लेने के बजाय पुलिस की सहायता लें, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

IMS लॉ कॉलेज में एआई एवं लॉ एजेंसी पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी

नोएडा। आईएमएस लॉ कॉलेज, नोएडा में एआई एवं लॉ ऑफ एजेंसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान देशभर से प्रतिभाशाली विधि विशेषज्ञों, शिक्षाविदों एवं विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एवं वॉक्सन यूनिवर्सिटी से संबद्ध प्रोफेसर डॉ. साल्वाटोर टोलोन अज्जारिटी ने अपने विचार साझा किए। अपने व्याख्यान में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पारंपरिक विधिक सिद्धांतों के बीच विकसित हो रहे संबंधों पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा भविष्य में विधि क्षेत्र में एआई की भूमिका पर महत्वपूर्ण चर्चा की। आईएमएस नोएडा के एडवाइजर प्रोफेसर डॉ. जे. के. शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे आधुनिक तकनीक और विधिक सिद्धांतों के समन्वय को समझें। यह पहल आईएमएस नोएडा की वैश्विक शैक्षणिक उत्कृष्टता एवं नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो छात्रों को बदलते विधिक परिदृश्य के अनुरूप तैयार करने में निरंतर अग्रसर है। आईएमएस नोएडा के डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ. गोविंद प्रसाद गोयल ने बताया कि इस ऑनलाइन संगोष्ठी में देशभर से लगभग 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

एमिटी विश्वविद्यालय में छात्रों को फेलोशिप अवसरों की दी गई जानकारी

नोएडा। एमिटी विवि में बुधवार को भारत सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के वैज्ञानिक सोहेल अहमद खान ने छात्रों और शोधार्थियों को विभिन्न फेलोशिप कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सा, क्लिनिकल और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्ध अनुसंधान अवसरों से विद्यार्थियों को अवगत कराना था। इस अवसर पर एमिटी ग्रुप वाइस चांसलर डा. गुरिंदर सिंह, एडिशनल प्रो वाइस चांसलर डा. चंद्रदीप टंडन और डीन डा. एस. के. श्रीवास्तव ने सोहेल अहमद खान का स्वागत किया।

सोहेल अहमद खान ने कहा कि स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की मानव संसाधन विकास योजना का उद्देश्य देश में कुशल स्वास्थ्य अनुसंधान कर्मियों का समूह तैयार करना है। इसके तहत मेडिकल छात्रों, वैज्ञानिकों और शिक्षकों को प्रशिक्षण, अनुसंधान परियोजनाओं और आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने अल्पकालिक छात्रवृत्ति, शोध सहायता कार्यक्रम, महिला वैज्ञानिक फेलोशिप, विदेश फेलोशिप और जैव-चिकित्सा अनुसंधान से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। डा. गुरिंदर सिंह ने कहा कि एमिटी विश्वविद्यालय अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में शामिल है। उन्होंने विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय के छात्र और शोधार्थी इन फेलोशिप योजनाओं का लाभ उठाएंगे।

डा. चंद्रदीप टंडन ने विश्वविद्यालय में संचालित अनुसंधान कार्यक्रमों और विभिन्न मिशनों की जानकारी साझा की। वहीं डा. एस. के. श्रीवास्तव ने शिक्षकों और शोधार्थियों से इस जानकारी को अन्य सहयोगियों तक पहुंचाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान सोहेल अहमद खान ने एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मॉलेक्यूलर मेडिसिन एंड स्टेम सेल रिसर्च तथा अन्य प्रयोगशालाओं का भी दौरा किया।

सीएम रेखा गुप्ता ने 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को दिखाई हरी झंडी

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय से 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन यूनिट्स का उद्देश्य भीषण गर्मी और हीटवेव के दौरान लोगों को राहत पहुंचाना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजधानी में लू के असर को कम करने के लिए तैयार किए गए 'हीट एक्शन प्लान 2026' की बुकलेट भी जारी की। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी और हीट वेव की चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली सरकार व्यापक और जन-केंद्रित कदम उठा रही है ताकि नागरिकों को बेहतर सुरक्षा और राहत मिल सके। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, समाज कल्याण मंत्री रवीन्द्र इन्द्राज सिंह उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि राहत को सीधे लोगों तक पहुंचाना है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने सभी 13 जिलों के लिए 13 विशेष मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स तैयार की हैं। ये यूनिट्स शहर के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराएंगी। 'गर्मी से जंग, दिल्ली सरकार के संग' केवल एक अभियान नहीं, बल्कि दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष का हीट एक्शन प्लान पूरी तैयारी और समन्वय के साथ लागू किया है। यह प्लान शहर के हर वर्ग और हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, विशेष रूप से दिहाड़ी और निर्माण श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, बेघर व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों जैसे संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने निर्माण कार्यों और खुले में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक बाहरी श्रम कार्यों को रोकने और विश्राम अवधि सुनिश्चित करने के निर्देश सार्वजनिक और निजी संस्थानों को दिए गए हैं। श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बच्चों को गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए सभी स्कूलों में 'वॉटर बेल सिस्टम' लागू किया गया है ताकि नियमित अंतराल पर बच्चों को पानी पीने के लिए प्रेरित किया जा सके। स्कूलों में दोपहर के समय आउटडोर गतिविधियों और असेंबली को भी रोक दिया गया है। इसके अतिरिक्त अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। राजधानी के 339 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओआरएस, आइस पैक और आवश्यक दवाइयों की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और विशेष 'कूल रूम' भी स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सरकारी भवनों में वाटर कूलर और पेयजल डिस्पेंसर लगाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। दिल्ली सरकार का हीट एक्शन प्लान केवल तात्कालिक राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जागरूकता अभियान, हरित क्षेत्र बढ़ाने, जल संरक्षण, शहरी तापमान नियंत्रण और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के विकास जैसे दीर्घकालिक उपाय भी शामिल हैं। सरकार द्वारा अलग-अलग माध्यमों से लोगों को हीटवेव से बचाव के उपायों के बारे में लगातार जागरूक किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे गर्मी के मौसम में अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अधिक से अधिक पानी पिएं, धूप में बाहर निकलने से बचें और आवश्यकता पड़ने पर 112 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स की सहायता प्राप्त करें। दिल्ली सरकार हर परिस्थिति में नागरिकों के साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भीषण गर्मी के दौरान कोई भी व्यक्ति राहत और सहायता से वंचित न रहे।

इन चीजों से लैस होंगी मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स : मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से नागरिकों को ठंडा और स्वच्छ पेयजल, ओआरएस पैकेट, प्राथमिक उपचार की सुविधा, कॉटन के गमछे और कैप उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक यूनिट में 400 से 500 लीटर क्षमता का ठंडे पानी का टैंक, फर्स्ट एड किट, ओआरएस वितरण व्यवस्था और आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध रहेगी। ये यूनिट्स प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक उन स्थानों पर संचालित होंगी जहां अधिक भीड़ और गर्मी का प्रभाव अधिक रहता है, जैसे श्रमिक चौक, बस अड्डे, बाजार, झुग्गी क्षेत्र और अन्य संवेदनशील इलाके। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जिले में 10 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है, जो अगले तीन महीनों तक इन मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के संचालन में सहयोग करेंगे। प्रत्येक जिले में प्रतिदिन लगभग 1000 ओआरएस पैकेट, 300 कॉटन गमछे और 200 कैप वितरित किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ईको-फ्रेंडली डिस्पोजेबल ग्लास और उचित वेस्ट कलेक्शन व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

एलजी और मुख्यमंत्री कॉलेज के 42वें वार्षिक समारोह में हुए शामिल

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यापाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसजीजीएससीसी) के 42वें वार्षिक समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद रहे।

उपराज्यपाल ने एआई और ज्ञान-आधारित परिवर्तन के इस युग में छात्रों से गुरुबानी के ज्ञान का अनुसरण करने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों से ज्ञान की खोज करना, उद्यमशीलता की भावना को पोषित करना और विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने को कहा। उपराज्यपाल ने कहा कि जब किसी संस्थान का संकल्प राष्ट्र के साथ जुड़ा होता है, तो उसकी उपलब्धियां राष्ट्र की उपलब्धियां बन जाती हैं। मुख्यमंत्री ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी।

उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर करते हुए कहा कि यह सम्मान छात्रों की मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास का सशक्त प्रमाण है। यह संस्थान अपनी उत्कृष्ट परंपरा के माध्यम से युवाओं में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण की भावना भी विकसित कर रहा है। उन्होंने सभी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य कामना की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कॉलेज का यह वार्षिक दिन विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए वैसा ही महत्व रखता है, जैसा एक किसान के लिए वैसाखी का पर्व। यह संस्थान सालों से बच्चों के भविष्य को संवारने का बेहतरीन काम कर रहा है।

संक्षिप्त खबरें

नांगलोई में गैर-कानूनी एलपीजी रिफिलिंग रैकेट का भंडाफोड़, 96 सिलेंडर जब्त

नई दिल्ली। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नांगलोई के बक्करवाला इलाके में गैर-कानूनी एलपीजी रिफिलिंग और जमाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। क्राइम ब्रांच ने पुलिस के साथ मिलकर खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की। इस दौरान 96 एलपीजी सिलेंडर के साथ-साथ इस गैर-कानूनी काम में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और सामान जब्त किए गए। साथ ही, रैकेट में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, इस गैर-कानूनी काम में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों को बिना इजाजत के स्टोर करना, उनमें छेड़छाड़ करना और उन्हें फिर से भरना शामिल था, जिन्हें कथित तौर पर ब्लैक मार्केटिंग और कीमत बढ़ाकर दूसरी जगह भेजा जा रहा था।

विवेक विहार अग्निकांड में नौ लोगों की मौत हादसा नहीं, सिस्टम की नाकामी : आप

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी(आप) के वरिष्ठ नेता एवं विधायक संजीव झा ने विवेक विहार स्थित एक पॉश कॉलोनी में लगी भीषण आग में जलकर नौ लोगों की मौत के लिए सिस्टम की नाकामी को जिम्मेदार बताया है। श्री झा ने बुधवार को कहा कि चंद दिन पहले पूर्वी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके विवेक विहार में आग लगने से नौ लोगों की मृत्यु हुई। दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी के पॉश इलाके में दमकल विभाग को सूचना देने के बावजूद अगर नौ लोगों की मौत हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसी की तो बनती ही है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पालम में एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई थी। वहां मौत इसलिए हुई थी क्योंकि दमकल विभाग के पास सुरक्षा जाल नहीं था जिस पर कूदकर लोग अपनी जान बचा पाते। बिना सुरक्षा जाल के कूदने के कारण कई लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग के पास हाइड्रोलिक सीढ़ियां भी नहीं थीं कि वे वहां तक पहुंच पाते।

महापौर ने सफ़ाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने बुधवार को सभी जोनल उपायुक्तों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। जिसमे दिल्ली में सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए ठोस और प्रभावी कार्ययोजना पर जोर दिया गया। बैठक में महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी जोन अपने-अपने क्षेत्रों में सफ़ाई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से और अधिक सुदृढ़ करें।

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई जाती है, वहां संबंधित कूड़ा प्रबंधन प्राइवेट एजेंसी की जवाबदेही तय की जाए| उन्होंने विशेष रूप से ज़ोन के सभी संवेदनशील स्थानों (वल्नरेबल प्वाइंट्स) की पहचान कर वहां नियमित और विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि जोन के सेनेटरी सुपरवाइजर (एसएस) और असिस्टेंट सेनेटरी इंस्पेक्टर (एएसआई) फील्ड में सक्रिय रूप से मौजूद रहकर सफाई कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि जमीनी स्तर पर प्रभावी सुधार दिखाई दे। सफाई कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए महापौर प्रवेश वाही ने एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा करते हुए कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और सफाई व्यवस्था में और सुधार आएगा। महापौर ने यह भी निर्देश दिया कि सभी सफ़ाई कर्मचारी अपनी वर्दी पहनकर कार्य करें, जिससे न केवल अनुशासन सुनिश्चित होगा बल्कि एमसीडी की सकारात्मक छवि भी मजबूत होगी। महापौर ने कहा कि रेहड़ी-पटरी को भी जागरूक किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके ठेलों एवं दुकानों के आसपास सफाई बनी रहे तथा किसी भी प्रकार का कूड़ा न फैलाया जाए।

बैठक में नालों की सफाई की भी विस्तृत समीक्षा की गई। प्रवेश वाही ने निर्देश दिए कि पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड सहित अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर नालों की सफ़ाई का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि जलभराव की समस्या से समय रहते निपटा जा सके। इसके अतिरिक्त महापौर ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और इस कार्य में दिल्ली पुलिस के सहयोग से प्रभावी अभियान चलाने पर जोर दिया। साथ ही अवैध मीट की दुकानों और अवैध डेयरियों के खिलाफ़ भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

नांगलोई में अवैध एलपीजी रीफिलिंग रैकेट का भंडाफोड़, तीन आरोपित गिरफ्तार

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नांगलोई के बक्करवाला इलाके में अवैध एलपीजी रीफिलिंग और कालाबाजारी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी कर 96 घरेलू गैस सिलेंडर, गैस ट्रांसफर करने के उपकरण, तीन वाहन और तौल मशीनें बरामद की हैं। इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार ने बुधवार को बताया कि, बक्करवाला रोड स्थित लक्ष्मी नगर इलाके में एक खाली प्लॉट में घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध तरीके से रीफिलिंग और भंडारण किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद विशेष टीम गठित कर छापा मारा गया। मौके पर एक नर्सरी के पीछे खाली प्लॉट में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर पड़े मिले। कुछ सिलेंडर वहां खड़े तीन टेंपो में लोड थे। पुलिस ने मौके से सुल्तानपुरी निवासी 37 वर्षीय विनोद, नजफगढ़ निवासी 38 वर्षीय विजय और कंझावला निवासी 26 वर्षीय वंश राज को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों गैस सिलेंडरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने बरामद सिलेंडरों को अवैध घोषित करते हुए जब्त कर लिया।

जांच में सामने आया कि आरोपी गैस एजेंसी से घरेलू एलपीजी सिलेंडर उठाकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के बजाय उन्हें खाली प्लॉट में जमा कर लेते थे। इसके बाद भरे सिलेंडरों से गैस निकालकर खाली सिलेंडरों में अवैध उपकरणों की मदद से रीफिलिंग की जाती थी। फिर इन्हें खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया जाता था। पुलिस के अनुसार, इस अवैध कारोबार से न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा था, बल्कि बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई थी। जिस स्थान पर रीफिलिंग की जा रही थी वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे और कभी भी आग या विस्फोट की घटना हो सकती थी। क्राइम ब्रांच ने आरोपितों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं तथा गैस एजेंसी के अन्य कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं या नहीं।

श्रीनिवासपुरी हादसे के बाद रिंग रोड पर जाम

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के रिंग रोड पर श्रीनिवासपुरी इलाके में एक कैंटर ने दो कारों को टक्कर मार दी, जिससे सर्विस लेन पूरी तरह बाधित हो गई। हादसे के बाद आश्रम से मूलचंद जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लग गया और यातायात प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों की आवाजाही सामान्य कराने का प्रयास शुरू किया। दुर्घटना के कारण सर्विस लेन बंद होने से कई वाहन चालक जाम में फंस गए। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल सर्विस लेन का उपयोग न करें और फ्लाईओवर के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचें।

कुख्यात लुटेरे 'बिलोरा-हड्डी' गिरफ्तार, दिल्ली की सड़कों पर मचा रखा था आतंक

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात लुटेरे बिलोरा-हड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने राजधानी की सड़कों पर लूटमारी का आतंक मचा रखा था। गिरफ्तारी के साथ ही चोरी का सामान और गाड़ियां भी बरामद की गई हैं।

पुलिस ने बुधवार को बताया- आरोपी संजू उर्फ 'बिलोरा' और सचिन उर्फ 'हड्डी' को मंगलवार को एक टिप-ऑफ के बाद बांस वाला पार्क इलाके से गिरफ्तार किया गया है। दोनों पहले जेल में बंद थे। इसी दौरान एक-दूसरे के संपर्क में आए और रिहा होने के बाद मिलकर लूटमारी को अंजाम देने लगे।

दिल्ली की सड़कों पर इस लुटेरी जोड़ी को 'बिलोरा-हड्डी' नाम से जाना जाने लगा। पुलिस ने कहा कि संजू और सचिन दोनों हिस्ट्रीशीटर हैं और 70 से ज़्यादा क्रिमिनल केस में शामिल पाए गए हैं। जांच करने वाले अधिकारी ने बताया- दोनों मिलकर लूट को अंजाम देते थे। ये दोनों ज्यादातर मामले में सोने की चेन पहनकर पैदल चलने वालों को निशाना बनाते थे।

विश्व अस्थमा दिवस पर विशेष: विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दी अस्थमा प्रबंधन की बीरीकियों पर जानकारी

कैलाश दीपक अस्पताल में सीएमई का आयोजन

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर कैलाश दीपक अस्पताल द्वारा आज विशेष सेमीनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अस्थमा के प्रति जागरूकता फैलाना और आधुनिक उपचार पद्धतियों से लोगों को अवगत कराना था।

विशेष सत्र में चिकित्सा पेशेवरों के साथ-साथ स्थानीय सोसायटियों के निवासियों, आरडब्ल्यूए के अध्यक्षों, सचिवों और अस्पताल में उपचाराधीन अस्थमा के मरीजों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रमुख विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के दौरान शहर के जाने-माने चेस्ट विशेषज्ञों ने अस्थमा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी।डॉ. सुशील कुमार उपाध्याय ने 'ब्रोंकियल अस्थमा को समझना' विषय पर चर्चा करते हुए इसके शुरुआती लक्षणों की पहचान पर जोर दिया। उन्होंने इसके बचाव के तरीके को भी लोगों को विस्तार से बताया।

डॉ. सुधीर कुमार गुप्ता ने 'एक्यूट अस्थमा का प्रबंधन' विषय पर बोलते हुए बताया कि अस्थमा के अचानक अटैक से घबराने की जरूरत नहीं है। अटैक के दौरान स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए इसके उपायों पर चर्चा की। डॉ. लवलीन शर्मा ने 'इनहेलर और अन्य उपकरण' विषय पर व्यावहारिक जानकारी साझा की और सही तकनीक के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि अस्थमा से डरने की जरूरत नहीं है। सही समय पर निदान और इनहेलर के सही इस्तेमाल से मरीज पूरी तरह सामान्य और सक्रिय जीवन जी सकता है।

इस महत्वपूर्ण चर्चा की अध्यक्षता इंटरनल मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञों डॉ. रजत जैन, डॉ. एल. रामचंद्रन और डॉ. दीप्ति चौधरी द्वारा की गई। सेमीनार के दूसरे दौर में संवादात्मक सत्र आयोजित कि या गया। इसमें आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों और मरीजों ने सीधे विशेषज्ञों से सवाल किए और अपनी शंकाओं को दूर किया।

डॉक्टरों ने इनहेलर के उपयोग को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर किया और बताया कि यह उपचार का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। कार्यक्रम के अंत में अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने सभी आगंतुकों को धन्यवाद दिया।

AI स्मार्ट चश्मों से बदलेगी ज़िंदगी: एम्स ने दृष्टिबाधित बच्चों को दी नई रोशनी

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। AI स्मार्ट चश्मों से बदलेगी ज़िंदगीः एम्स ने दृष्टिबाधित बच्चों को दी नई रोशनी जनभावना टाइम्स नई दिल्ली। देश में दृष्टिबाधित लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एम्स दिल्ली के डॉ. आर.पी. सेंटर ने AI-पावर्ड स्मार्ट विज़न ग्लासेस वितरित किए।

इस पहल का उद्देश्य दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी दैनिक ज़िंदगी की चुनौतियों को कम करना है। भारत में अनुमानित तौर पर करीब 7 लाख लोग ऐसे हैं जो अपरिवर्तनीय अंधता या गंभीर दृष्टि बाधा से जूझ रहे हैं। यह समस्या न केवल स्वास्थ्य से जुड़ी है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी गहरा असर डालती है। इस चुनौती से निपटने के लिए AI तकनीक से लैस स्मार्ट चश्मे एक नई उम्मीद बनकर सामने आए हैं। ये डिवाइस कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आसपास की जानकारी को रियल-टाइम ऑडियो में बदलते हैं। इसमें टेक्स्ट-टू-स्पीच, चेहरे और वस्तुओं की पहचान, रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाना, नेविगेशन और इमरजेंसी सपोर्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह कार्यक्रम डॉ. आर.पी. सेंटर, एम्स नई दिल्ली द्वारा Rotary District 3012, SHG और Vision-Aid के सहयोग से आयोजित किया गया। लाभार्थियों को केवल डिवाइस ही नहीं, बल्कि इसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण और लगातार सहयोग भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रो. राधिका टंडन ने कहा कि AI आधारित सहायक तकनीक से मरीजों की निर्भरता कम होगी और उनकी स्वतंत्रता बढ़ेगी।

इससे शिक्षा, रोजगार और रोजमर्रा की ज़िंदगी में नए अवसर खुलेंगे। वहीं प्रो. प्रवीण वशिष्ठ ने जानकारी दी कि जनवरी 2026 में 53 लाभार्थियों को ये चश्मे दिए गए थे और अब 40 और दृष्टिबाधित बच्चों को इसका लाभ मिला है। अब तक दिल्ली-NCR के करीब 1500 बच्चों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है।

प्रो. तनुज दादा ने कहा कि नई तकनीक का उपयोग करके दृष्टिबाधित लोगों की कार्यक्षमता बढ़ाना समय की जरूरत है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 की गवर्नर डॉ. अमिता मोहिंद्रू ने इसे एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और भविष्य में और अधिक लोगों तक पहुंचने की दिशा में काम जारी रहेगा। आयोजकों ने भरोसा दिलाया कि इस पहल को आगे बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी दृष्टिबाधित बच्चा पीछे न रह जाए।

संपादकीय

नहीं बदला पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र

पश्चिम बंगाल में भारी केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद चुनाव तो लगभग हिंसा-मुक्त रहे लेकिन चुनावी नतीजों के बाद राज्य के विभिन्न इलाक़ों में हिंसा का दौर जारी है। जो इस बात का सुबूत है कि सत्ता परिवर्तन के बाद भी राज्य का पुरान 'रक्तचरित्र' नहीं बदला है। सत्ता में भारी बदलाव के बाद , कई इलाकों से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। नतीजे घोषित होने के 48 घंटे बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमलों और हिंसा में मौत का सिलसिला जारी है। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने गुलाल के बजाए जीत का जश्न खून से मनाया। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जला दिए गए। इसके अलावा कई इलाकों में भाजपा कार्यालयों में तोड़फोड़ के बाद उन्हें आग के हवाले किया गया। ताजा हिंसा में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने अपने दो-दो समर्थकों की मौत का दावा किया है। आरामबाग इलाके में भी राजनीतिक हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। वहां भी भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद वहां आग लगाई गई। ऐसी ही एक और घटना नंदीग्राम से भी सामने आई है।ममता बनर्जी की हार के बाद वहां शुबेंदु अधिकारी के वाहन को निशाना बनाया गया। सोनारपुर में भी भाजपा के एक कार्यकर्ता की पीट-पीट की जान ले ली गई। आसनसोल इलाक़े में भाजपा कार्यालय में आगजनी की गई। कई अन्य इलाक़ों से भी ऐसी ही ख़बरें देखने को मिल रही हैं। कहीं-कहीं तृणमूल कांग्रेस के दफ़्तर में लगे झंडे हटाकर वहां भाजपा के झंडे लगाने या उन्हें गेरुआ रंग में रंगने के समाचार आ रहे हैं। कई जगह तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों पर भी हमले, आगजनी, तोड़फोड़ और पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले की ख़बरें भी सामने आ रही हैं। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद ने असामाजिक तत्वों को हिंसा से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने विजय जुलूस में बुलडोज़र शामिल करने पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य के शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ़्तारी के निर्देश दिए हैं। हिंसा की ताजा घटनाओं के बीच पश्चिम बंगाल में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। जबकि भाजपा का कहना है कि यह तृणमूल कांग्रेस का हमेशा से हिंसा की पक्षधर रही है और हार उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ममता बनर्जी अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। बतौर मुख्यमंत्री यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस को यह संदेश दें कि उन्हें जनादेश को स्वीकार करना चाहिए।

सियासत का नया व्याकरण लिखता जनादेश 2026

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए 'महाभूकंप' को देखे बिना 2026 के इस जनादेश की व्याख्या अधूरी है। लगभग डेढ़ दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस का ढहना और भाजपा का 150 सीटों के पार जाना यह दर्शाता है कि बंगाल की जनता 'सिंडिकेट राज' और 'कट मनी' की संस्कृति से ऊब चुकी थी। बंगाल का यह परिणाम केवल एक चुनावी जीत नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति है, जहां मतदाताओं ने 'बंगाली अस्मिता' के साथ 'राष्ट्रीय विकास' के समन्वय को स्वीकार किया है। संदेशखाली जैसी घटनाओं ने शासन के प्रति जो आक्रोश पैदा किया था, वह ईवीएम के माध्यम से ज्वालामुखी की तरह फटा। भाजपा ने यहां जिस प्रकार से हिंदू मतों का ध्रुवीकरण किया और साथ ही मतुआ एवं राजवंशी समुदायों को अपने पक्ष में संगठित किया, उसने टीएमसी के अभेद्य दुर्ग की ईंट से ईंट बजा दी। ग्रामीण बंगाल में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' और 'जल जीवन मिशन' जैसी केंद्रीय योजनाओं ने एक नया 'लाभार्थी वर्ग' तैयार किया, जिसने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की पारदर्शिता को राज्य सरकार की भ्रष्टाचार युक्त मशीनरी से बेहतर पाया।

-योगेश कुमार गोयल-

2026 के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता वापसी की घटना मात्र नहीं हैं बल्कि ये देश की राजनैतिक दिशा और मतदाता के बदलते मनोविज्ञान का एक ऐसा विस्तृत दस्तावेज हैं, जिसने भविष्य की राजनीति के लिए नए प्रतिमान स्थापित कर दिए हैं। इन परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय मतदाता अब केवल भावनात्मक नारों या पारंपरिक वोट बैंक के गणित में उलझने वाला नहीं है बल्कि वह शासन की जवाबदेही, नेतृत्व की विश्वसनीयता और विकास के ठोस धरातल पर अपना निर्णय सुना रहा है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण के तटीय मैदानों तक फैली इस राजनैतिक हलचल का यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि 'भगवा' राजनीति का पूर्वी विस्तार अब अपने चरम पर है जबकि दक्षिण में क्षेत्रीय अस्मिता और नए राजनैतिक विजन के बीच एक दिलचस्प संघर्ष छिड़ गया है। ये चुनाव परिणाम उन तमाम राजनैतिक पंडितों के लिए एक सबक हैं, जो केवल पुराने आंकड़ों के आधार पर भविष्यवाणियां करते थे क्योंकि इस बार मतदाताओं ने एक ऐसी 'परिवर्तन की आंधी' का सूत्रपात किया है, जिसने कई दिग्गजों के राजनैतिक भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए 'महाभूकंप' को देखे बिना 2026 के इस जनादेश की व्याख्या अधूरी है। लगभग डेढ़ दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस का ढहना और भाजपा का 150 सीटों के पार जाना यह दर्शाता है कि बंगाल की जनता 'सिंडिकेट राज' और 'कट मनी' की संस्कृति से ऊब चुकी थी। बंगाल का यह परिणाम केवल एक चुनावी जीत नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति है, जहां मतदाताओं ने 'बंगाली अस्मिता' के साथ 'राष्ट्रीय विकास' के समन्वय को स्वीकार किया है। संदेशखाली जैसी घटनाओं ने शासन के प्रति जो आक्रोश पैदा किया था, वह ईवीएम के माध्यम से ज्वालामुखी की तरह फटा। भाजपा ने यहां जिस प्रकार से हिंदू मतों का ध्रुवीकरण किया और साथ ही मतुआ एवं राजवंशी समुदायों को अपने पक्ष में संगठित किया, उसने टीएमसी के अभेद्य दुर्ग की ईंट से ईंट बजा दी। ग्रामीण बंगाल में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' और 'जल जीवन मिशन' जैसी केंद्रीय योजनाओं ने एक नया 'लाभार्थी वर्ग' तैयार किया, जिसने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की पारदर्शिता को राज्य सरकार की भ्रष्टाचार युक्त मशीनरी से बेहतर पाया। यह चुनाव परिणाम ममता बनर्जी के उस करिश्मे के अंत का भी संकेत है, जो कभी अपराजेय माना जाता था और अब बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां सुशासन और कानून-व्यवस्था ही सत्ता की एकमात्र कसौटी रह गई है।

असम की ओर रुख करें तो यहां की स्थिति बंगाल से बिल्कुल भिन्न लेकिन उतनी ही प्रभावशाली है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा की 'हैट्रिक' ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब विकास को सांस्कृतिक अस्मिता के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह एक अजेय फॉर्मूला बन जाता है। असम में भाजपा की जीत केवल सत्ता की निरंतरता नहीं है बल्कि यह उस विश्वास की पुष्टि है, जो जनता ने सरमा के प्रभावी और साहसी नेतृत्व में दिखाया है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन ने राजनैतिक भूगोल को इस तरह बदला कि घुसपैठ और बाहरी प्रभाव की राजनीति हाशिए पर चली गई और 'असमिया राष्ट्रवाद' का नया स्वरूप उभरकर सामने आया। 'ओरुनोडोई' जैसी योजनाओं ने महिला मतदाताओं के बीच भाजपा को एक ऐसे रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया है, जिसके पास उनके दैनिक जीवन की समस्याओं का ठोस समाधान है। असम का जनादेश संदेश देता है कि यदि नेतृत्व के पास विजन हो और वह जमीनी मुद्दों पर आक्रामक तरीके से कार्य करे तो जनता उसे फिर सेवा का अवसर प्रदान करती है। यहां विपक्ष की बिखरी हुई ताकत और कांग्रेस की वैचारिक शून्यता ने भाजपा की राह को और भी आसान बना दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पूर्वोत्तर में भाजपा अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक स्थायी शक्ति बन चुकी है।

दक्षिण भारत के राजनैतिक परिदृश्य में तमिलनाडु ने इस बार पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। थलपति विजय के रूप में एक नए राजनैतिक सूर्य का उदय यह बताता है कि तमिलनाडु की जनता अब डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने द्वंद्व से मुक्ति चाहती थी। विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' द्वारा 100 सीटों का आंकड़ा पार करना एक राजनैतिक चमत्कार है, जिसने एमजीआर के उस दौर की याद ताजा कर दी, जब सिनेमा और राजनीति का संगम सत्ता की चाबी बन गया था। विजय ने खुद को केवल एक फिल्मी सितारे के रूप में नहीं, एक 'संकटमोचक' और 'युवा आइकन' के रूप में पेश किया। उन्होंने गठबंधन की राजनीति को ठेंगा दिखाते हुए 'अकेले शेर' की तरह चुनावी मैदान में उतरने का जो साहस दिखाया, उसने तमिल युवाओं के बीच एक नई ऊर्जा का संचार किया। यह परिणाम कमल हासन और विजयकांत जैसे पूर्ववर्ती सितारों की तुलना में कहीं अधिक गहरा है क्योंकि विजय ने 'बौद्धिक राजनीति' के बजाय 'जमीनी और मास-अपील' वाली राजनीति को चुना। तमिलनाडु का यह जनादेश द्रविड़ राजनीति के भविष्य को एक नई दिशा देने वाला है, जहां अब 'तीसरी शक्ति' केवल संभावना नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुकी है।

केरल का चुनाव परिणाम भी कम दिलचस्प नहीं रहा, जहां 'एक बार इधर, एक बार उधर' की पारंपरिक रीत ने पिनाराई विजयन की तमाम कोशिशों के बावजूद एलडीएफ को सत्ता से बाहर कर दिया। यूडीएफ की यह प्रचंड वापसी यह दर्शाती है कि केरल का शिक्षित मतदाता भ्रष्टाचार और राजकोषीय कुप्रबंधन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। विभिन्न घोटालों ने एलडीएफ की नैतिक साख को जो चोट पहुंचाई, उसकी भरपाई उसकी जनहितैषी योजनाओं से भी नहीं हो सकी। राहुल गांधी की वायनाड में सक्रियता और 'न्याय' जैसी योजनाओं के वादे ने कांग्रेस नीत यूडीएफ के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच उपजे असंतोष ने सत्ता के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया। केरल का मतदाता यह संदेश दे रहा है कि वह किसी भी दल को 'टेकन फॉर ग्रांटेड' नहीं लेता और सत्ता की चाबी हमेशा जनता के हाथ में रहती है, जो हर पांच साल में शासन की समीक्षा बड़ी निर्ममता से करती है।

पुडुचेरी जैसे छोटे केंद्रशासित प्रदेश ने भी यह दिखाया कि राजनीति में स्थिरता और केंद्र के साथ तालमेल का कितना महत्व है। एन. रंगासामी की सहज छवि और भाजपा के साथ उनके गठबंधन ने मतदाताओं को यह भरोसा दिलाया कि विकास के लिए केंद्र और स्थानीय सरकार का एक पटरी पर होना जरूरी है। पुडुचेरी के परिणामों ने यह साबित किया कि छोटे क्षेत्रों में व्यक्तिगत संपर्क और सामाजिक समीकरण ही हार-जीत की रेखा खींचते हैं। यहां का मतदाता प्रशासनिक गतिरोध के बजाय स्थिरता को अधिक महत्व देता है और यही कारण रहा कि गठबंधन की राजनीति ने यहां अपनी सफलता का परचम फहराया।

पांचों राज्यों के परिणामों को यदि एक व्यापक कैनवास पर रखकर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति अब 'परफॉर्मेंस' के युग में प्रवेश कर चुकी है। अब केवल जातिगत समीकरण बैठाकर या बड़े-बड़े विज्ञापन देकर चुनाव नहीं जीते जा सकते। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत और असम में उसकी वापसी दर्शाती है कि 'हिंदुत्व' और 'विकास' का मिश्रण अभी भी भारतीय राजनीति का सबसे शक्तिशाली तत्व है लेकिन तमिलनाडु और केरल के परिणाम यह भी सचेत करते हैं कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं और स्थानीय नेतृत्व का महत्व कभी कम नहीं होगा। इन चुनावों ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के लिए केरल में संजीवनी का काम किया है तो वहीं भाजपा के लिए दक्षिण में नए मित्र तलाशने की चुनौती पेश की है। कुल मिलाकर, 2026 के इस जनादेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता अब अधिक अपेक्षा-केंद्रित हो गया है। वह केवल यह नहीं देखता कि सरकार ने क्या किया बल्कि यह भी देखता है कि नेतृत्व कितना विश्वसनीय है और भविष्य के लिए उसके पास क्या रोडमैप है। थलपति विजय जैसे नए चेहरों का स्वागत और ममता बनर्जी जैसे कद्दावर नेताओं की हार बताती है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। आने वाले समय में वही दल और नेता प्रासंगिक रहेंगे जो जनता की आकांक्षाओं को समझेंगे और विकास, पहचान एवं सुशासन के बीच एक कुशल संतुलन स्थापित कर सकेंगे।

रवीन्द्रनाथ टैगोर जयंती (7 मई) पर विशेष: भारत की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक हैं टैगोर

-सुनील कुमार महला-

गुरूदेव रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को बंगाल के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवार में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के घर हुआ था। बचपन से ही असाधारण और बेहद संवेदनशील प्रतिभा के धनी टैगोर ने मात्र 8 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिख दी थी और बहुत कम लोग जानते होंगे कि शुरुआत में वे 'भानुसिंह' उपनाम से लिखते थे। उन्हें चारदीवारी वाली पारंपरिक स्कूली शिक्षा बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उनकी अधिकांश शिक्षा घर पर ही स्वाध्याय और निजी शिक्षकों के माध्यम से हुई। इसी स्वाध्याय के बल पर उन्होंने संस्कृत, भारतीय दर्शन और नक्षत्र-विज्ञान का गहन अध्ययन किया। वर्ष 1877 में कानून की पढ़ाई के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, परंतु वहां के शैक्षणिक माहौल से संतुष्ट न होने के कारण, वे बिना कोई डिग्री लिए भारत लौट आए। टैगोर एक ऐसे बहुमुखी रचनाकार थे, जिन्होंने कविता, संगीत, नाटक, कहानी और चित्रकला-हर क्षेत्र पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की शानदार व दमदार रचना की, जिन्हें आज 'रवींद्र संगीत' के नाम से जाना जाता है, जो बंगाली संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।

पाठक जानते होंगे कि उनकी कालजयी साहित्यिक कृति 'गीतांजलि' (गीतों का उपहार) मूल रूप से बंगाली में लिखी गई थी तथा यह 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुई थी। जब टैगोर ने स्वयं इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, तब महान आयरिश कवि डब्ल्यू. बी. यीट्स(अंग्रेजी साहित्यकार) इसके अनुवाद से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने इस पुस्तक की ऐतिहासिक प्रस्तावना लिखी। इसी कृति के लिए टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च 'नोबेल पुरस्कार' प्राप्त हुआ और वे यह सम्मान पाने वाले पहले गैर-यूरोपीय बने। इसी वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें 'डी-लिट्' की उपाधि से भी सम्मानित किया। वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 'नाइटहुड' (सर) की मानद उपाधि दी, जिसे उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अत्यंत क्षोभ के साथ वापस लौटा दिया।

टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनीं- भारत का 'जन-गण-मन' और बांग्लादेश का 'आमार सोनार बांग्ला'। इसके अलावा, श्रीलंका के राष्ट्रगान 'श्रीलंका माथा' के रचयिता आनंद समराकून भी शांतिनिकेतन में टैगोर के ही शिष्य थे, जिन्होंने गुरुदेव की संगीत शैली से प्रेरित होकर इसकी रचना की थी। यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि भारत के राष्ट्रगान को लेकर कुछ समय यह विवाद भी उठा कि यह ब्रिटिश राजा की प्रशंसा में लिखा गया है, परंतु बाद में यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया कि यह मूल रूप से भारत की अंतरात्मा और उसके गौरव को समर्पित है। बहरहाल, यहां पाठकों को यह भी जानकारी देता चलूं कि रवींद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच का आत्मीय संबंध भी ऐतिहासिक है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी को सबसे पहले 'महात्मा' की उपाधि टैगोर ने ही दी थी, जबकि गांधीजी ने उन्हें आदरपूर्वक 'गुरुदेव' कहकर पुकारा था। पाठक शायद यह बात नहीं जानते होंगे कि टैगोर ने अपनी पत्नी और बच्चों की असामयिक मृत्यु के गहरे आघात को झेला, जिसने उनके लेखन में संवेदनशीलता और आध्यात्मिक गहराई को और अधिक बढ़ा दिया। उन्होंने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ विज्ञान और दर्शन के गूढ़ विषयों पर प्रसिद्ध संवाद किए। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्रकला की शुरुआत की। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वे 'रेड-ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस' (लाल और हरे रंग को ठीक से न पहचान पाने की शारीरिक सीमा) से ग्रसित थे, लेकिन इस बाधा को पार करते हुए उन्होंने लगभग 3, 000 पेंटिंग्स बनाईं। रंगों की इस सीमा के कारण ही उन्होंने चमकीले रंगों के बजाय डार्क शेड्स और म्यूट टोन का उपयोग किया, जिसने उनकी कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई।

सामाजिक मोर्चे पर, वे अंधविश्वासों के घोर विरोधी थे और उन्होंने बंगाल के पुनर्जागरण में अग्रणी भूमिका निभाते हुए बाल विवाह, छुआछूत और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का कड़ा विरोध किया। अपनी कहानियों 'काबुलीवाला' और 'चोखेर बाली', जो बहुत पठनीय व प्रसिद्ध रहीं हैं, के जरिए उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और मानवीय संवेदनाओं को स्वर दिया। इतना ही नहीं, यह भी जानकारी मिलती है कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय उन्होंने हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए 'राखी' को एकता के एक बड़े सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में स्थापित किया। बहुत कम लोग यह बात जानते होंगे कि स्वतंत्रता के बाद, वर्ष 1948 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, जिससे वे भारतीय डाक टिकट पर स्थान पाने वाले पहले गैर-राजनीतिक व्यक्तित्व बने। इसके अतिरिक्त, टैगोर का यह मानना था कि 'मानवता' राष्ट्रवाद से कहीं ऊपर है और वे अंध राष्ट्रवाद के कड़े आलोचक थे। इसी वैश्विक दृष्टिकोण और विश्वबंधुत्व की भावना के साथ उन्होंने यूरोप, अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों की यात्राएं कीं। वे बंगाल के प्रसिद्ध सूफी संत और बाउल गायक लालन फकीर के मानवतावादी व सांप्रदायिक सौहार्द के संदेशों से गहरे प्रभावित थे, जिसकी झलक उनके आध्यात्मिक चिंतन में मिलती है।

उनका शिक्षा दर्शन प्रकृति की गोद में, चारदीवारी से मुक्त सहज विकास पर आधारित था। इसी उद्देश्य से उन्होंने 22 सितंबर 1921 को 'विश्वभारती' नामक शैक्षिक संस्थान (शांतिनिकेतन) की स्थापना की, जिसके विकास के लिए उन्होंने लगातार 20 वर्षों तक अथक प्रयास किया और नोबेल पुरस्कार से मिली पूरी राशि इसमें लगा दी। वे पश्चिम के विज्ञान, तकनीक व तर्कशीलता को पूर्व के अध्यात्म, शांति व मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ना चाहते थे। इसी तालमेल को दर्शाने के लिए उन्होंने विश्वभारती का ध्येय वाक्य 'यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्' (जहाँ पूरा विश्व एक घोंसला बन जाता है) रखा था। वास्तव में, उनका शिक्षा दर्शन बाल-केंद्रित था और वे चाहते थे कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा केवल उनकी मातृभाषा में ही हो। उन्होंने सीखने के लिए 'लर्निंग बाइ डूइंग' (करके सीखना) और 'भ्रमण विधि' को सर्वश्रेष्ठ माना। उनके पाठ्यक्रम में केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि खेलकूद, बागवानी, ड्राइंग, गायन, नृत्य, प्रयोगशाला कार्य और छात्र-स्वशासन जैसी गतिविधियां शामिल थीं। सच तो यह है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन अत्यंत व्यापक, मानवतावादी और प्रकृति-केन्द्रित था। वे मानते थे कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य व्यक्ति के समग्र विकास (शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक) को सुनिश्चित करना है।

ईश्वर पर विश्वास करना

क्या आप जानते हैं, छह दर्शनों में से पहले तीन दर्शन तो भगवान के बारे में बात तक नहीं करते, न्याय, वैशेषिक और सांख्य दर्शन। गौतम महर्षि के द्वारा रचित न्याय दर्शन ज्ञान के बारे में चर्चा करता है कि आपका ज्ञान सही है या नहीं। ज्ञान के माध्यम को जानना कि वह सही है या नहीं, यह है न्याय दर्शन। उदाहरण के लिए, आप अपनी इंद्रियों के द्वारा ये देख पाते हैं कि सूर्य ढल रहा है या सूर्य निकल रहा है। लेकिन न्याय दर्शन कहता है, 'नहीं' आप केवल उस पर विश्वास नहीं कर सकते, जो आप देख रहे हैं, आपको उससे परे जाकर खोजना है कि क्या वास्तव में सूर्य ढल रहा है या फिर पृथ्वी घूम रही है।

धर्मकर्म

वैशेषिक दर्शन- हमें लगता है कि कोपरनिकस ने यह खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, मगर यह बिलकुल असत्य है। उन्होंने जरूर पता लगाया था, लेकिन उसके पहले, भारत में बहुत लंबे समय से लोग यह बात जानते थे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है।

न्याय दर्शन इन सबके बारे में बात करता है। वह बात करता है धारणाओं की और उन धारणाओं के संशोधन की। और फिर आता है वैशेषिक दर्शन, यह संसार की सभी वस्तुओं की गिनती करता है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर सारी वस्तुएं एवं विषय और इन सबका विश्लेषण। यह है वैशेषिक दर्शन। इसमें वे मन, चेतना, बुद्धि, स्मृति इत्यादि के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद है सांख्य दर्शन। तो ये तीन दर्शन ईश्वर के बारे में बात नहीं करते, बल्कि वे चेतना के बारे में बात करते हैं। केवल योग सूत्रों में जो कि चौथा दर्शन है वे ईश्वर के विषय पर चर्चा करते हैं।

इसलिए, आपको ईश्वर पर विश्वास करने के लिए विवश महसूस नहीं करना है, लेकिन आपको किसी पर तो विश्वास करना होगा। आपको कम से कम चेतना पर तो विश्वास करना होगा।

आज का इतिहास

1663 - लंदन में ड्रूरी लेन स्थित 'रॉयल' नाम का पहला थियेटर खुला।
1697 - स्टॉकहोम के शाही महल, 13 वीं शताब्दी में वापस डेटिंग, एक बड़ी आग में धोया गया; वर्तमान शाही महल का खाका केवल कुछ हफ़्ते बाद प्रस्तुत किया गया था।
1727 - रूस की महारानी कैथरीन प्रथम ने यूक्रेन से यहूदियों को बाहर करने का आदेश दिया।
1748 - फ्रेंच सैनिकों ने ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध में मास्ट्रिच को जीता।
1763 - ओटावा मूल अमेरिकी जनजाति के पोंटियाक ने पोंटियाक युद्ध की शुरुआत को चिह्नित करते हुए, ब्रिटिश से फोर्ट डेट्रोइट को जब्त करने का प्रयास किया।
1763 - मुख्य पोंटिआक ने फोर्ट डेट्रॉइट में ब्रिटिश बलों पर हमला करके “पोंटिक का षडयंत्र” शुरू किया।
1771 - शमूएल हर्न ने कनाडा की कॉपर मीन नदी की खोज की
1775 - तुर्की राज्य बुकोविना ऑस्ट्रिया से अलग किया गया।
1785 - फ़्राँसिसी नागरिक जॉन प्येर फ़्राँसुआ ब्लनशार ने अमरीकी नागरिक जॉन जैफ़्रिज के साथ पहली बार एक गुब्बारे में बैठकर इंगलिश चैनल को पार किया।
1794 - फ्रांसीसी क्रांतिः मैक्सिमिलियन रोबेस्पिएरे ने फ्रेंच फर्स्ट रिपब्लिक के नए राज्य धर्म के रूप में सुप्रीम की पंथ की स्थापना की।
1832 - लंदन की संधि ग्रीस को स्वतंत्र राज्य बनाया, ओटो ऑफ़ विटल्सबैच, बावरिया के राजकुमार, को राजा चुना गया। इस प्रकार आधुनिक ग्रीस का इतिहास शुरू हुआ।
1832 - यूनान ने स्वतंत्रता हासिल की, बावारिया को सम्राट चुना गया।
1875 - जापान और रूस के बीच सेंट पीटर्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
1895 - अलेक्जेंडर स्टेपानोविच पोपोव ने अपने रेडियो रिसीवर को प्रस्तुत किया, जिसे लाइटनिंग डिटेक्टर के रूप में परिष्कृत किया गया, रूसी भौतिक और रासायनिक सुरक्षा के लिए।

सियासत की अपनी अलग इक ज़ुबाँ है

-निर्मल रानी-

जनता को सब्ज़ बाग़ दिखाने में पूरी महारत रखने वाले सत्ताधारी नेताओं से यदि देश के हालात के बारे में बात कीजिये तो अपनी लच्छेदार बातों से यह साबित कर देंगे कि देश में चारों तरफ़ बाग़ों में बहार है, जनता ख़ुशहाल है, क़ानून व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, देश में विकास की गंगोत्री बह रही है। और यदि किसी ने सरकार की आलोचना करने की कोशिश की तो चुनाव में बार बार मिलने वाली विजय का हवाला देते हुये उल्टे उसी से यह पूछ लिया जाता है कि यदि जनता संतुष्ट नहीं तो बार बार विभिन्न राज्यों में जनादेश व जनसमर्थन सत्ता के पक्ष में क्यों? आप चीख़ते चिल्लाते रहिये कि चुनाव परिणाम को सत्ता के पक्ष में प्रभावित करने में मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग, एस आई आर, इनकम टैक्स, सी बी आई, ई डी, बी एस एफ़, सी आर पी, गोदी मीडिया आदि संस्थाओं की भूमिका रही है।

परन्तु आपकी शिकायत सुन कौन रहा है? याद कीजिये 2013 में, जब डॉलर के मुक़ाबले रुपया 60 के स्तर पर पहुंचा था उस समय नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि रुपये की गिरती क़ीमत से सरकार की प्रतिष्ठा गिर रही है। तब मोदी ने रुपये की कमज़ोरी को यूपीए सरकार की दिशाहीन नीतियों और आर्थिक संकट का संकेत बताया था। 'कमज़ोर रुपया = कमज़ोर सरकार' का कथन प्रचारित किया गया था। मोदी ने उस समय यह भी कहा था कि गिरते रुपये के कारण देश के व्यापारी बोझ नहीं सह पाएंगे और विश्व व्यापार में भारत पीछे रह जाएगा।

परन्तु आज तो मोदी शासन काल में डॉलर के मुक़ाबले वही रुपया 95.18 तक पहुँच चुका है। परन्तु शायद आज न तो यह स्थिति सरकार की दिशाहीन नीतियों की वजह से है न ही यह आर्थिक संकट का संकेत है। न ही यह कमज़ोर सरकार का लक्षण है न ही रुपये की गिरती क़ीमत से सरकार की प्रतिष्ठा गिर रही है। बजाये इसके अक्टूबर 2022 में जब रुपया 1 डॉलर के मुक़ाबले 82 पर पहुंचा था उस समय अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह तर्क ज़रूर दिया था कि 'भारतीय रुपया गिर नहीं रहा है, बल्कि अमेरिकी डॉलर तेज़ी से मज़बूत हो रहा है'। क्या यह तर्क 2014 से पहले यू पी ए सरकार के समय लागू नहीं हो सकता था? परन्तु शायद उस समय के सत्ताधारियों और आज के विपक्ष में न तो इस तरह के 'कुतर्क रुपी तर्क' देने की 'सलाहियत' थी न ही मीडिया मैनेज कर इस विषय को हंगामा बनाने से रोकने की कला। इसलिए 1 डॉलर के 100 रूपये के आंकड़े को छूने के क़रीब होने बावजूद आज यह चर्चा का विषय ही नहीं है?

इसी तरह 2004-2014 के बीच जब देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार थी। उस दौरान पेट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस के दाम बढ़ने पर भाजपा ने देश भर में ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किए थे। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर इनके अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने की तस्वीरें भी सामने आई थीं। 2010 से 2014 के बीच भाजपाई यह प्रदर्शन उस दौर में कर रहे थे जबकि पेट्रोल की क़ीमतें 61रूपये से लेकर 70 रूपये प्रति लीटर के क़रीब थीं। और घरेलू रसोई गैस की क़ीमत 414 के क़रीब थीं। उस समय कई भाजपा नेता सिलेंडर की क़ीमतों में वृद्धि के विरोध में सड़कों पर चूल्हे जलाकर प्रदर्शन किया करते थे। परन्तु आज पेट्रोल व डीज़ल कहीं 100 रूपये के क़रीब तो कहीं 100 रूपये पार कर चुका है। गैस का मूल्य भी 1000 प्रति सिलिंडर के क़रीब हो गया है। परन्तु न तो विपक्ष का हंगामा न हंगामे में शोर या उसका असर न ही ऐसी ख़बरों को मीडिया में कोई स्थान। आजकल तो वैसे भी ईरान इस्राईल युद्ध के चलते देश में अनेक जगहों पर गैस सिलिंडर लेने के लिये लोग लंबी लंबी क़तारों में खड़े हुये हैं। गैस की धड़ल्ले से ब्लैक मेलिंग हो रही है। परन्तु जनता के हितों से मुख्य रूप से जुड़े ऐसे सवालों पर तो कोई चर्चा नहीं है।

इसी तरह भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में एक नया वोट बैंक तैयार किया है 'लाभार्थी वोट बैंक'। प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना के तहत देशभर में लगभग 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों अर्थात देश की लगभग 57% आबादी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को हर महीने प्रति सदस्य 5 किलोग्राम मुफ्त गेहूं या चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। आलोचक इस योजना को सरकार की नाकामी बता रहे हैं। इनका कहना है कि इस योजना का मतलब है कि देश की 57% आबादी इतने पैसे भी नहीं कमा पा रही कि वह अपने व परिवार के लिये 5 किलो राशन तक ख़रीद सके। जबकि कुछ आलोचक कहते हैं कि ऐसी योजनायें लोगों को निठल्ला बनाती हैं। कोई कुछ भी कहता रहे परन्तु सरकार ऐसी योजनाओं को चलाकर अपनी पीठ थपथपाती है और इसके बदले इन्हीं लाभार्थियों से वोट की उम्मीद लगाये रहती है। और धन्य है देश की वह जनता भी जो आत्मनिर्भर होने या सरकार से रोज़गार के अवसर मांगने के बजाये इसी 5 किलो मुफ़्त राशन को ही अपना भाग्य समझकर फूले नहीं समाती। यह सफल अन्दाज़-ए-सियासत की ही एक बानगी कही जाएगी कि आज जी एस टी व नोटबंदी से परेशान लोग व व्यवसायी इस विषय पर चर्चा बंद कर चुके हैं। लॉक डाउन के दौर में हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने वाले लोग अपना दुःख भूलने को मजबूर हो चुके हैं। मंहगाई, बेरोज़गारी, स्वास्थ्य, शिक्षा व नारी स्मिता तो जैसे कोई मुद्दा ही नहीं।

वास्तव में देश की राजनीति अब उस दौर में प्रवेश कर चुकी है जहाँ जनता के मुद्दे क्या हैं और क्या होंगे यह भी अब जनता नहीं बल्कि राजनैतिक दलों के नेता तय करते हैं। इसलिये जनता की आधारभूत ज़रूरतें और लोकहितकारी बातें छोड़िए और पाकिस्तान, हिन्दू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, घुसपैठिया, लव जिहाद, जाति धर्म, धर्म विशेष की कथित रूप से बढ़ती जनसंख्या जैसे सत्ता द्वारा निर्धारित विषयों को ही वर्तमान राजनीति की सबसे बड़ी ज़रुरत स्वीकार कीजिये। शायद इन्हीं हालात के मद्देनज़र मशहूर शायर बशीर बद्र साहब को कहना पड़ा कि किताबें, रिसाले न अख़बार पढ़ना। मगर दिल को हर रात इक बार पढ़ना। सियासत की अपनी अलग इक ज़ुबाँ है। लिखा हो जो इक़रार, इनकार पढ़ना।।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर -7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व बी-142/2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 से प्रकाशित।
संपादकीय एवं संपर्क कार्यालय ए-152 सेक्टर-63, नोएडा-201301 संपादक - आदित्य वशिष्ठ कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई. DELHIN/2012/42452
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यालयों में एसएमसी पर नए दिशा-निर्देश किए जारी

माध्यमिक स्तर तक विस्तार और पारदर्शिता पर खास जोर

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों में पहली बार माध्यमिक स्तर तक एसएमसी का विस्तार, एक महीने के भीतर गठन की अनिवार्यता और पारदर्शी कार्यप्रणाली जैसे कई अहम बदलाव किए गए हैं।

स्कूल प्रबंधन समिति के दिशानिर्देशों को जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए, हमारे देश में लगभग 15 लाख स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों में, स्कूल प्रबंधन समिति छात्रों, शिक्षकों और समाज के बीच एक सेतु का काम करेगी। हम शिक्षा और स्कूल प्रबंधन को समाज के हाथों में सौंपने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) को लेकर व्यापक संशोधित दिशा-निर्देश 2026 जारी किए हैं, जो पहले जारी सभी गाइडलाइंस को प्रतिस्थापित करेंगे। नए निर्देशों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब एसएमसी केवल प्राथमिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कक्षा 12 तक के माध्यमिक विद्यालयों में भी लागू की जाएगी। इसके साथ ही विद्यालय प्रबंधन विकास समिति (एसएमडीसी) की जगह एसएमसी को लागू करने का प्रावधान किया गया है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के एक महीने के भीतर एसएमसी का गठन करना अनिवार्य होगा। समिति के सदस्यों की संख्या बच्चों के नामांकन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अधिकतम 100 विद्यार्थी पर 12-15 सदस्य, 100-500 विद्यार्थी पर 15-20 सदस्य और 500 से अधिक विद्यार्थी पर 20-25 सदस्यों की अनुमानित संख्या निर्धारित की जा सकेगी। एसएमसी के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। किसी सदस्य को एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है लेकिन एक सदस्य लगातार दो कार्यकाल से अधिक कार्य नहीं कर सकता, सिवाय सदस्य सचिव के जोकि स्कूल के प्राचार्य होंगे। एसएमसी के गठन के बाद नई समिति की पहली बैठक अगले कार्यदिवस या अधिकतम एक सप्ताह के भीतर आयोजित की जा सकती है।

पहली बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। नई व्यवस्था में समिति की संरचना को अधिक समावेशी बनाया गया है। इसमें 75 प्रतिशत सदस्य बच्चों के अभिभावक या संरक्षक होंगे, जबकि शेष 25 प्रतिशत में स्थानीय प्राधिकरण, शिक्षक, शिक्षाविद्, विषय विशेषज्ञ, अकादमिक, वरिष्ठ एवं पूर्व विद्यार्थी और समुदाय के अग्रिम कार्यकर्ता जैसे आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ता और सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) जो विद्यालय के आसपास कार्यरत हों।

महिला भागीदारी को बढ़ावा देते हुए समिति में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं का होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अब एसएमसी की नियमित मासिक बैठक अनिवार्य होगी और बैठक के एजेंडा, उपस्थिति और निर्णयों का रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा। इसके अलावा, विद्यालय रिपोर्ट कार्ड (यूडीआईएसई+) को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का भी प्रावधान जोड़ा गया है। नए दिशा-निर्देशों में एसएमसी की भूमिका को भी विस्तारित किया गया है। अब समिति केवल निगरानी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्कूल विकास योजना (एसडीपी) तैयार करने, सीएसआर के जरिए संसाधन जुटाने, ड्रॉपआउट बच्चों को मुख्यधारा में लाने और आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (एफएलएन) लक्ष्यों को हासिल करने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। इसके अलावा, दो नई उप-समितियों—विद्यालय भवन समिति और शैक्षणिक समिति—के गठन का प्रावधान किया गया है, जिससे कार्यों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार का मानना है कि इन नए दिशा-निर्देशों से स्कूलों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ेगी, पारदर्शिता मजबूत होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार उल्लेखनीय है कि विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय संचालन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। इसके प्रमुख कार्यों में विद्यालय के समग्र कार्यों की निगरानी और शैक्षणिक योजनाओं जैसे समग्र शिक्षा योजना, पीएम श्री और पीएम पोषण के समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन की देख-रेख शामिल हैं।

जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन आज सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी

● रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार शाम पांच बजे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी फिल्म रिलीज करेंगे

जयपुर। जयपुर मिलिट्री स्टेशन स्थित मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान में संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में देश की सैन्य रणनीति, समन्वय और सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री होंगे, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) और थल, जल एवं वायु सेना के प्रमुख भी इसमें भाग लेंगे।

सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम 7 मई को होगा। सुबह 9 बजे मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में ग्रुप फोटो सेशन और संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का औपचारिक आयोजन किया जाएगा। इसी दिन सुबह 10:45 बजे सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ के अवसर पर विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में रक्षा और सैन्य उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि सम्मेलन को लेकर जयपुर मिलिट्री स्टेशन में सुरक्षा और प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

हल्दीघाटी गेट और सप्त शक्ति गेट से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए विशेष समन्वय व्यवस्था बनाई गई है। यह सम्मेलन देश की सामरिक तैयारियों, सैन्य समन्वय और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें उच्चस्तरीय सैन्य नेतृत्व भविष्य की रणनीतियों पर मंथन करेगा। भारतीय सेना ने 7 मई, 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था।

'इंडिया' गठबंधन जल्द ही टूट जाएगा, इसका कारण राहुल गांधी होंगे: भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'अयोग्य नेता' बताते हुए कहा कि वह 'इंडिया' गठबंधन का संचालन करने में असमर्थ हैं तथा उनके नेतृत्व के कारण विपक्षी गठबंधन टूटने के कगार पर है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने चुनावों में 'वोट चोरी' का आरोप लगाने को लेकर गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो स्वयं चोर होते हैं वे दूसरों को भी चोर समझते हैं।

पात्रा की यह टिप्पणी गांधी द्वारा 'एक्स' पर किए गए उस पोस्ट के बाद आई है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि लोकसभा में भाजपा के 240 सांसदों में से लगभग हर छठा सांसद 'वोट चोरी' के जरिए जीता है। गांधी ने 'एक्स' पर लिखा कि उनकी पहचान करना मुश्किल नहीं है – क्या हमें उन्हें भाजपा की अपनी भाषा में 'घुसपैठिए' कहना चाहिए? और हरियाणा? वहां तो पूरी सरकार ही 'घुसपैठिया' है। उन्होंने लिखा कि वोट चोरी से कभी सीट छीन ली जाती हैं, कभी पूरी सरकारें ही गिर जाती हैं। उनका असली डर सच्चाई है। क्योंकि अगर निष्पक्ष चुनाव होते, तो आज भी वे 140 सीट नहीं जीत पाते। इसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता ने हरियाणा की जनता द्वारा भाजपा सरकार को दिए गए जनादेश का अपमान किया है।

पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने आज पोस्ट किया कि न सिर्फ वोट और सीट चोरी हो रही हैं, बल्कि अब पूरी सरकार ही चोरी हो गई है। क्या यह कोई सरकार है या आपके जीजा की कोई जमीन जिसे चुराया जा सकता है? चोर तो हर किसी को चोर ही समझता है। भाजपा सांसद ने गांधी द्वारा कथित तौर पर हरियाणा सरकार को 'घुसपैठियों की सरकार' कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने पूछा कि जनता ने मतदान किया और यह भाजपा की सरकार है। विधायक जनता द्वारा चुने गए हैं और मुख्यमंत्री भी जनता द्वारा चुने गए हैं। ऐसे में उन्हें घुसपैठिया कहना कैसे सही है? पात्रा ने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन आंतरिक रूप से बिखर रहा है और यह गठबंधन कुछ ही हफ्तों में टूट जाएगा तथा इसके लिए गांधी जिम्मेदार होंगे।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, आप एक अयोग्य नेता हैं, और इसी वजह से आज आपकी पूरी पार्टी पतन की ओर है तथा बिखर रही है। और आज, भाजपा के मंच से, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ: बस कुछ हफ्तों का इंतजार कीजिए, 'इंडी' गठबंधन टूट जाएगा। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि 'इंडी' गठबंधन टूटने वाला है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम यह बात यूं ही नहीं कह रहे हैं। पात्रा ने पत्रकारों से कहा कि और इसका सारा दोष राहुल गांधी पर आएगा। जब ऐसा होगा, तब शायद वह विदेश में होंगे, इसलिए यह उनके लिए चिंता का विषय नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी के नेतृत्व ने न केवल कांग्रेस को बल्कि समग्र विपक्षी गठबंधन को भी कमजोर कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता ने अरविंद केजरीवाल तथा ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और उन पर चुनावी हार के बाद एकजुट होने का आरोप लगाया।

देशभर में घरेलू रसोई गैस का वितरण सामान्य: सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि देशभर में घरेलू रसोई गैस का वितरण सामान्य है और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से कोई ड्राई-आउट की खबर नहीं है। सरकार ने कहा कि लगभग 95 फीसदी गैस सिलिंडर का वितरण 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' के जरिए पूरी की जा रही है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) का वितरण सामान्य बना हुआ है, और स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि लगभग 95 फीसदी गैस सिलिंडर का वितरण 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' के जरिए पूरा किया जा रहा है। साथ ही पिछले दो दिनों में 88.82 लाख बुकिंग के मुकाबले लगभग 87.28 लाख सिलेंडर डिलीवर किए गए हैं। सुजाता शर्मा ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट के बीच खाना पकाने के लिए सरकार घरेलू रसोई गैस की 100 फीसदी आपूर्ति उपभोक्ताओं तक सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और कमर्शियल

सिलेंडरों के उपभोक्ताओं को 70 फीसदी तक आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। संयुक्त सचिव ने बताया कि लगभग 6 लाख 31 हजार नए पीएनजी कनेक्शनों में गैस सप्लाई शुरू हो गई है और 2.67 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि अब तक 6 लाख 93 हजार उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शनों के लिए रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने कहा कि 49 हजार से जयादा पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपनी LPG कनेक्शन स्वेच्छा से सरेंडर कर दिए हैं। सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले दो दिनों में लगभग 15,900 टन कमर्शियल एलपीजी और 876 टन ऑटो एलपीजी की बिक्री दर्ज की गई है। इसके अलावा लगभग 1.2 लाख 5 किलो वाले सिलिंडर भी बेचे गए हैं। वहीं, 3 अप्रैल से अब तक 10,000 से ज्यादा जागरूकता कैंप लगाए गए हैं, जिनके दौरान अब तक 1.84 लाख से ज्यादा 5 किलो वाले सिलिंडर बेचे जा चुके हैं। शर्मा ने यह भी बताया कि कामकाज और रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से चल रहे हैं।

वहीं, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र के हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है, ताकि नाविकों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके और समुद्री परिचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहे।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 48 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों या भारतीय नाविकों को ले जा रहे विदेशी ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी किसी भी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। ओपेश कुमार शर्मा ने कहा कि डीजी शिपिंग के कंट्रोल रूम ने शुरू होने के बाद से अब तक 8,570 कॉल और 18,732 से अधिक ईमेल संभाले हैं। इनमें से 156 कॉल और 668 ईमेल पिछले 48 घंटों के दौरान आए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से 2,999 से अधिक नाविकों की सुरक्षित वापसी में भी मदद की है, जिनमें से 23 नाविकों की वापसी पिछले 48 घंटों में हुई है। पूरे भारत में बंदरगाहों का परिचालन सामान्य बना हुआ है, और कहीं भी भीड़भाड़ की कोई रिपोर्ट नहीं है।

BFCL ने पृथ्वी दिवस पर दोहराई विकास की प्रतिबद्धता

रामगढ़। पृथ्वी दिवस पर बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग्स लिमिटेड (बीएफसीएल) ने आवर पावर, आवर प्लानेट थीम पर एचएएसपी परिसर में स्कॉलर्स हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने सस्टेनेबिलिटी विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया।

बच्चों ने अपने अभिनय के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा बचत जैसे मुद्दों को सरल और प्रेरणादायक तरीके से दर्शाया। एचएएसपी और जीएफए इकाइयों में आयोजित जागरूकता सत्रों में कर्मचारियों और अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इन सत्रों में पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और सतत विकास की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों को अपने दैनिक कार्यों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में बीएफसीएल के डायरेक्टर गौरव बुधिया ने कहा कि सस्टेनेबिलिटी केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति एक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि कंपनी अपने कैप्टिव पावर प्लांट के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने जैसे प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रही है।

37 किलो गांजा के साथ तीन अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

धमतरी। ओड़िशा से खरीदकर कार के डिक्की में छिपाकर महाराष्ट्र-नासिक गांजा ले जा रहे तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से 37.800 किलोग्राम गांजा जब्त कर तीनों के खिलाफ कार्रवाई उपरांत बुधवार को जेल भेज दिया है। पुलिस लगातार गांजा तस्करों पर शिकंजा कस रहा है, इससे गांजा के अवैध कारोबार से जुड़े माफियों में दहशत है। पिछले 24 घंटों में पुलिस ने नगरी क्षेत्र से 92.770 किलो गांजा जब्त कर कार्रवाई किया है। नगरी ब्लॉक के प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद खत्म होने के बाद पुलिस अब सिर्फ गांजा तस्करों को पकड़ने जुटी हुई है। इसके लिए पिछले दिनों नवरंगपुर ओड़िशा के बोरई, कुन्दई एवं कोंडागांव के विश्रामपुरी ट्राई-जंक्शन पर अंतर्राज्यीय समन्वय को मजबूत कर रणनीतिक रूप से चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं।

हमीरपुर के मौदहा बांध के खोले गए फाटक, जल निकासी शुरू

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर मौदहा बांध के गेटों के निरीक्षण एवं आवश्यक मरम्मत कार्य के दृष्टिगत बांध को आंशिक रूप से खाली किए जाने की प्रक्रिया बुधवार को प्रारंभ कर दी गई है।

अधिशाषी अभियंता दिनेश कुमार ने बुधवार को बताया कि 15 मई 2026 तक बांध से निरंतर जल प्रवाह के कारण बिरमा नदी के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ने की पूर्ण संभावना है। इससे नदी के तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों, किसानों एवं पशुधन पर प्रभाव पड़ सकता है। जनहित एवं जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। प्रभावित क्षेत्रों में मुनादी एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। नदी तट के समीप रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने तथा अनावश्यक रूप से नदी के पास न जाने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि पशुधन, कृषि यंत्र एवं अन्य आवश्यक सामग्री को सुरक्षित स्थानों पर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन, पुलिस एवं आपदा प्रबंधन की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं।

पंच परिवर्तन के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा संघ : आलोक कुमार

शिमला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह आलोक कुमार ने कहा कि संघ अपने शताब्दी वर्ष में 'पंच परिवर्तन' के पांच प्रमुख विषयों कुटुंब प्रबोधन, स्व की भावना, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्य पर विशेष रूप से कार्य करेगा, जिससे समाज में सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाया जा सके।

शिमला में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए आलोक कुमार ने कहा कि बीते वर्षों में देश की परिस्थितियों में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि लगभग दो दशक पहले देश के कई हिस्सों में जाने में लोगों को डर लगता था, जबकि आज स्थिति में सुधार हुआ है। कश्मीर के लाल चौक का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जहां पहले कोई सार्वजनिक उत्सव मनाना मुश्किल था, वहीं अब लोग रात में भी नए साल का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने संघ के इतिहास का उल्लेख करते हुए बताया कि हजारों स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और विभाजन के दौरान विस्थापितों की सहायता के लिए तीन हजार से अधिक शिविर लगाए।

उन्होंने कहा कि एक छोटे संगठन के लिए यह बहुत बड़ा कार्य था। इसके अलावा गोवा और हैदराबाद के आंदोलनों में भी संघ की भूमिका रही और देश के विभिन्न हिस्सों में संगठन ने सक्रिय रूप से काम किया। आलोक कुमार ने कहा कि संघ देश की सभी भाषाओं को राष्ट्रीय मानता है, जिससे उसे व्यापक स्वीकार्यता मिली है। पंजाब में कठिन परिस्थितियों के दौरान भी संघ ने कार्य किया और भारत माता की जय को जन-जन का नारा बनाया। उन्होंने पंच परिवर्तन के पांच विषयों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कुटुंब प्रबोधन के तहत परिवारों को सशक्त बनाना, संस्कार देना और परंपराओं का निर्वहन सुनिश्चित करना जरूरी है।

"स्व" की भावना पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश आज आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है और कई देशों को अनाज व बिजली उपलब्ध करा रहा है। पर्यावरण संरक्षण पर उन्होंने विशेष चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शिमला जैसे शहर, जो सीमित आबादी के लिए बने थे, आज अत्यधिक दबाव झेल रहे हैं। जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि नदियों का प्रदूषण गंभीर समस्या बन चुका है और छोटे-छोटे प्रयासों से इसे सुधारा जा सकता है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि इस बार कुंभ में प्लास्टिक के बर्तनों के उपयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। सामाजिक समरसता के विषय पर उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव मानवता के विरुद्ध है और समाज में सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। साथ ही नागरिक कर्तव्य बोध पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ शताब्दी वर्ष के अवसर पर इन पांच विषयों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

डीआरडीओ ने दिल्ली में सीबीआरएन फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र खोला

नई दिल्ली। रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों का मुकाबला करने के लिए राजधानी में बुधवार को एक फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र खोला गया है। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने किया।

डीआरडीओ के मुताबिक इस प्रशिक्षण और प्रदर्शन केंद्र में विभिन्न अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। यहां रेडियोलॉजिकल और परमाणु परीक्षण सुविधा के साथ ही आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया और वास्तविक समय फील्ड प्रतिक्रिया इकाइयां भी होंगी। यह केंद्र 'इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज' के तहत आने वाले सीबीआरएन उत्कृष्टता केंद्र का एक हिस्सा है। इस केंद्र में रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सीबीआरएन आपात स्थितियों की तैयारी तथा संकट प्रतिक्रिया में शामिल विभिन्न अन्य एजेंसियों को प्रभावी प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इस केंद्र में प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से विशेषज्ञों की अगली पीढ़ी को तैयार किया जा सकेगा, ताकि वे इस कार्य को अग्रिम पंक्ति तक ले जा सकें और साथ ही नवीनतम तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाकर इस क्षेत्र को और समृद्ध बना सकें। उद्घाटन समारोह में 'सैनिक सहायता प्रणाली' के महानिदेशक डॉ. उपेंद्र कुमार सिंह, 'उत्पादन समन्वय और सेवा संपर्क' की महानिदेशक डॉ. (श्रीमती) चंद्रिका कौशिक, 'संसाधन और प्रबंधन' के महानिदेशक डॉ. रविंद्र सिंह और कॉर्पोरेट निदेशकों के साथ-साथ अन्य अधिकारी और वैज्ञानिक उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश के रक्षा गलियारों में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश: योगी आदित्यनाथ

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के छह रक्षा औद्योगिक गलियारों लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट के लिए 35,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां न्यू कैंट में आयोजित तीन दिवसीय 'नॉर्थटेक सिंपोजियम' के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक बड़ा भूमि बैंक तैयार किया है।

रक्षा और वैमानिकी नीति के माध्यम से निवेश के इच्छुक निवेशकों को प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में छोटे हथियारों, रक्षा उपकरणों और सैन्य सामग्रियों के उत्पादन के रूप में यह केंद्र उभरा है। इसके साथ ही परंपरागत रूप से 'पूर्व का मैनचेस्टर' कहलाने वाला कानपुर गोला-बारूद, मिसाइल, डिफेंस टेक्सटाइल और प्रोटेक्टिव गियर के विनिर्माण का केंद्र बिंदु बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल और भारी रक्षा विनिर्माण पर ध्यान दिया गया है। चित्रकूट और आगरा को वैमानिकी और रक्षा में सटीक इंजीनियरिंग के गढ़ के रूप में विकसित किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि सैनिकों की क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारों में तोप के गोले, ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट और उन्नत संचार प्रणालियों का विनिर्माण किया जा रहा है। रक्षा विनिर्माण गलियारे के लिए आवश्यक सहयोग उत्तर प्रदेश में मौजूद है मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर ड्रोन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 21,000 से अधिक स्टार्टअप विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हुए हैं।

इनमें एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर आदि क्षेत्रों के स्टार्टअप शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजबूत पारितंत्र का निर्माण हुआ। आज हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे, हाइवे, रेल संपर्क, मेट्रो और हवाई संपर्क के रूप में सबसे अच्छा आधारभूत ढांचा उत्तर प्रदेश के पास है।'नॉर्थटेक सिंपोजियम' का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चार मई को किया था। इसमें रक्षा क्षेत्र में कार्यरत 250 से अधिक कंपनियों ने अपने उत्पाद एवं प्रौद्योगिकियां पेश कीं।

मुख्यमंत्री ने कालभैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन

वाराणसी। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को वाराणसी पहुंचे। गोरखपुर से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उतरा तो वहां पहले से मौजूद भाजपा के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अफसरों ने मुख्यमंत्री की अगवानी की। पुलिस लाइन से मुख्यमंत्री कड़ी सुरक्षा के बीच वाहनों के काफिले में बड़ा लालपुर स्थित उदय प्रताप कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉ. राजीव कृष्ण के घर पहुंच कर मांगलिक समारोह में शामिल हुए। यहां परिजनों से कुछ देर बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी और महिलाओं व बच्चों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनके साथ सामूहिक फोटो भी खिचाई।

इसके बाद वे कालभैरव मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने बाबा की आरती भी की। कालभैरव मंदिर से दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी विधिवत पूजन अर्चन किया। बाबा के पावन ज्योर्तिलिंग का अभिषेक कर उन्होंने देश प्रदेश में जीवन मंगल की कामना की। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र) प्रभार रविन्द्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु', एमएलसी हंसराज ा, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिणी विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी,कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, पिंडरा विधायक डॉ अवधेश सिंह भी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मंगलवार शाम को ही काशी आने वाले थे। लेकिन गोरखपुर में शिक्षामित्रों के चेक वितरण कार्यक्रम में देर होने के कारण उनका दौरा रद्द हो गया था। शहर में मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए उनके कार्यक्रम स्थल और आवागमन वाले मार्ग को नो-फ्लाई जोन घोषित करने के साथ सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया है। पुलिस लाइन से बड़ालालपुर जाने के दौरान रास्ते में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ता सड़क किनारे खड़े थे। नटिनिया दाई मंदिर के समीप कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के वाहन पर पुष्प वर्षा की।

हर जरूरतमंद का बनवाएं आयुष्मान कार्ड : मुख्यमंत्री योगी

गोरखपुर। सीएमयोगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा और आश्वस्त किया कि सरकार इलाज कराने में भरपूर मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद, पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े।

महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी करीब 200 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनीं। उनके प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर समस्या, शिकायत का संज्ञान लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वे परेशान न हों, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। उन्होंने अलग-अलग मामलों के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित करते हुए निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद निस्तारण होना चाहिए। जनता दर्शन में हर बार की तरह बुधवार को भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे।

मुख्यमंत्री ने उनसे आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा, साथ ही भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। अस्पताल का एस्टीमेट मिलते ही विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की हर पीड़ा का निवारण सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता नहीं होनी चाहिए।जनता दर्शन में कुछ महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी आए थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों को प्यार किया और उन्हें आशीर्वाद के साथ चॉकलेट दी। इस दौरान उन्होंने एक महिला के साथ आए दो बच्चों से हंसी-ठिठोली भी की और उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया।

क्रास फायरिंग में 7 शातिर बदमाश गिरफ्तार, तीन अपराधी घायल

रायबरेली। बुधवार को दो अलग-अलग हुई दो मुठभेड़ों में पुलिस ने सात शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस की जबाबी फायरिंग में तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से जल जीवन मिशन से लूटी गईं दस बोरा पीतल की टोंटियां समेत कई असलहे बरामद किए हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि बुधवार की तड़के करीब 2 बजे मुखबिर की सटीक सूचना पर जब पुलिस ने डीह थाना क्षेत्र में डीह कस्बे के पास घेराबंदी करने पर कार सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरु कर दी। जवाबी कार्यवाही में कार सवार अक्षत मिश्रा और मोहित आर्या के पैर में गोली लगी और इनके साथ ही इनके अन्य तीन साथियों संतोष, अभिषेक और अरविंद को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आलोक सिंह के अनुसार इन बदमाशों ने जल जीवन मिशन के गोदाम पर धावा बोलकर पीतल की टोंटियां लूटी थीं और दो चौकीदारों को लहूलुहान कर दिया था। इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पांच टीमें गठित की गई थीं।

उन्होंने बताया कि यह मुठभेड़ चल ही रही थी कि भदोखर थाना क्षेत्र में नहर भदोखर नहर पुलिया के पास भी बदमाशों के होने की खबर मिली। पुलिस ने जब इन्हें रोकने का प्रयास किया तो फायरिंग शुरु हो गई। जिसमें सराय मानिक निवासी प्रयागराज साहू पुलिस की गोली से घायल हो गया जबकि उसका साथी डीह निवासी सूरज गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से जल जीवन मिशन से लूटी गईं दस बोरा पीतल की टोंटियां, तीन अवैध तमंचा , दो जिंदा कारतूस और तीन खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक चार पहिया वाहन व एक ई-रिक्शा लोडर बरामद किया है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

सोनभद्र। हाथीनाला थाना क्षेत्र स्थित मुर्धवा-हाथीनाला मार्ग पर बुधवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक मंगलवार की रात में एक बारात में शामिल होने रेणुकूट आए थे और आज भोर में वापस घर लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक, साऊडीह हाथीनाला निवासी अकलवंत (26) और हथवानी निवासी अजय कुमार (25) मंगलवार की रात एक बारात में शामिल होने रेणुकूट आए थे। आज भोर में करीब तीन बजे दोनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे। अभी वह दोनों मुर्धवा-हाथीनाला रोड पर पहुंचे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम भेजकर मामले की जानकारी परिवार को देते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई।

बच्चे से कुकर्म और हत्या का आरोपी मुठभेड़ में मारा गया, एसओजी प्रभारी घायल

हरदोई। मल्लावां क्षेत्र में सात वर्षीय एक लड़के से कुकर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में आरोपी 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश बुधवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अधिकारी के अनुसार मुठभेड़ के दौरान पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) के प्रभारी भी घायल हो गए।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि मल्लावां थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को मक्के के खेत से एक बच्चे का शव बरामद किया गया था और मुख्य आरोपी के तौर पर इनामी बदमाश मेहनूर (32) की पहचान की गई। मीणा ने बताया कि बुधवार को आरोपी की थाना क्षेत्र में मौजूदगी की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने उसे घेर लिया, लेकिन आरोपी ने पुलिस दल पर गोली चला दी। उन्होंने कहा, ''पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मेहनूर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान एसओजी प्रभारी राजेश कुमार को भी गोली लगी है और उनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह मामला अपहरण के बाद कुकर्म और हत्या का प्रतीत होता है। आरोपी ने जांच को भटकाने और पकड़े जाने से बचने के लिए चोरी के सिम कार्ड से बच्चे के परिजनों को फिरौती का फोन भी किया था, ताकि मामला केवल अपहरण का लगे। बच्चे का शव मिलने के बाद लखनऊ क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

कन्नौज जिले का निवासी मेहनूर एक आदतन अपराधी था और विभिन्न जनपदों में उस पर करीब एक दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से एक 32 बोर की पिस्तौल, एक .315 बोर का तमंचा, एक मोटरसाइकिल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं।

सड़क हादसे में जान गवाने वाले पुलिसकर्मियों के शव पहुंचे जालौन, एडीजी की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ वीर सपूतों को दी गई अंतिम विदाई

उरई। हरियाणा के नूंह जनपद में मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को गहरे शोक में डुबो दिया। जालौन के चार पुलिसकर्मी अपहरण केस में दबिश देने के लिए नूंह स्कॉर्पियो कार से गए हुए थे, इस दौरान एक्सप्रेस वे पर उनकी कार ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित होकर अन्य वाहन से टकरा गई थी। इस दर्दनाक दुर्घटना में जालौन में तैनात दो दरोगा- सत्यभान और मोहित यादव तथा दो सिपाही प्रदीप और अशोक सहित कुल पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई थी।

बता दें कि बुधवार की सुबह सभी दिवंगत पुलिसकर्मियों के पार्थिव शरीर उरई स्थित पुलिस लाइन लाए गए, जहां का माहौल बेहद गमगीन रहा। साथी पुलिसकर्मियों की आंखें नम थीं और हर कोई अपने वीर साथियों को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा। सुबह करीब 10 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद पुलिसकर्मियों को अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान कानपुर जोन के एडीजी आलोक सिंह, झांसी रेंज के आईजी आकाश कुलहरी, जालौन के पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय तथा अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अंतिम सलामी के बाद सभी पुलिसकर्मियों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांवों के लिए रवाना कर दिए गए, जहां पूरे सम्मान और विधि-विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस लाइन में बड़ी संख्या में अधिकारी और जवान अपने साथियों को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। वहीं, एडीजी आलोक सिंह ने कहा ये हमारे अपने सपूत हैं, जो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं। पूरा विभाग उनके परिवार के साथ खड़ा है। उनका बलिदान कभी अमिट नहीं होगा।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत

देवरिया। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की बुधवार को मौत हो गई। कोतवाली प्रभारी के अनुसार विठलपुर गांव की निवासी चानमती (80), पत्नी रामधारी, किसी काम से जा रही थीं तभी डहरौली के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला को स्थानीय लोगों की सूचना पर 108 एंबुलेंस की मदद से महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है।

उच्च न्यायालय ने मथुरा में भीड़ प्रबंधन के लिए समग्र योजना की जानकारी तलब की

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में पर्व-त्योहार पर भगदड़ जैसी घटनाओं में जनहानि पर संज्ञान लेते हुए मथुरा जिला प्रशासन से पूछा है कि क्या उनके पास शहर के लिए भीड़ और संकट प्रबंधन की कोई व्यापक योजना मौजूद है।

स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने भीड़ से जुड़ी आपदाओं से निपटने के लिए रणनीतियों और प्रबंधन सिद्धांतों का भी विवरण मांगा है जिसमें प्रशिक्षण और जागरुकता के जरिए संस्थागत क्षमता बढ़ाई जा सके। स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज ने राज्य सरकार और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि अधिकारी मनमाने और भेदभावपूर्ण ढंग से चुन-चुनकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कथित अनधिकृत निर्माणों के लिए 23 लोगों के खिलाफ विध्वंस आदेश पारित किए गए हैं, लेकिन ऐसी विध्वंस कार्यवाही चुनिंदा रूप से केवल याचिकाकर्ता और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ ही निष्पादित की गई है।

उच्च न्यायालय में मंगलवार को एमवीडीए को एक समग्र हलफनामा दाखिल करने के लिए एक अंतिम अवसर दिया और सभी 23 संपत्तियों से जुड़ी ध्वस्तीकरण की कार्यवाहियों के संबंध में स्थिति और कार्रवाई जैसे मुद्दे पर विवरण मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनधिकृत निर्माण के लिए चिह्नित संपत्तियों की संख्या और विवरण के बारे में भी बताने को कहा है। इसके अलावा, अनधिकृत निर्माण रोकने के लिए अपनाई गई नीति, दिशानिर्देश और मानक परिचालन प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी मांगी है। अदालत ने कहा कि अनधिकृत निर्माण से भगदड़ जैसी स्थितियों में बचाव कार्यों में व्यवधान पैदा होता है।

इसलिए मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट यह बताएं कि भीड़ का व्यवहार समझने, स्पष्ट परिभाषित भूमिका और जिम्मेदारी के साथ भागीदारों के बीच समन्वय के लिए क्या कोई विशेषज्ञ निकाय इस जिले में मौजूद है। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 19 मई 2026 को करेगी।

पेड़ से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका के शव, 7 मई को युवती की थी शादी

शाहजहांपुर। जिले के परौर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका मिला। सबसे ज्यादा मर्माहत करने वाली बात यह है कि जिस युवती का शव मिला, उसकी 07 मई को बारात आनी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक (देहात) भंवरे दीक्षा अरुण ने बताया कि जिन युवक-युवती का शव पेड़ से लटका पाया गया। उनकी शिनाख्त कुबेरपुर गांव निवासी सोवेंद्र (19) और गांव के ही रहने वाली युवती (19) के रूप में हुई है। गांव वालों का कहना है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। घरवालों ने लड़की की शादी तय कर दी थी। सात मई को बारात आनी थी, जिसको लेकर घर में तैयारियां चर रही थीं। वहीं, युवती प्रेमी से शादी करना चाहती थी। आशंका है कि इसी कारण उसने अपने प्रेमी के साथ गांव से कुछ दूरी पर एक आम के पेड़ से फंदे के सहारे फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों परिवारों के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच कर रही है।

बच्ची की भावुक अपील का हुआ असर, मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी

लखीमपुर खीरी। जिले की रहने वाली छह वर्षीय मानवी सिंह की अपने घर के पास जलभराव वाली सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर की गयी भावुक अपील के बाद जिलाधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर समस्या के समाधान के आदेश दिये।

लखीमपुर शहर के पास सलेमपुर कोन गांव की पहली कक्षा की छात्रा मानवी सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट को संबोधित करते हुए एक छोटा-सा वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया था, जो वायरल हो गया। बच्ची ने अपने संदेश में कहा ''डीएम अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। प्लीज, मेरे घर के पास वाली सड़क को ठीक करवा दीजिए।'' उसने इसके साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें वह अपने घर की ओर जाने वाली ईंटों से बनी जलमग्न सड़क पर पानी में से होकर गुजर रही थी। मानवी की यह मासूमियत भरी अपील न सिर्फ वायरल हुई, बल्कि सीधे लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह की नजर में भी आ गई। जिलाधिकारी जलभराव की समस्या के प्रति बच्ची की संजीदगी से बेहद प्रभावित हुए और उससे खुद मिलकर उसकी शिकायत के बारे में जानने के लिये अधिकारियों की एक टीम के साथ गांव पहुंचे। जिलाधिकारी ने मानवी से बात की और उसे बिस्किट व मिठाइयां देने के साथ ही उसकी शिकायत का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। सड़क का मुआयना करने पर जिलाधिकारी को पता चला कि मानवी के घर को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली ईंटों की सड़क पूरी तरह से ऊबड़-खाबड़ और खराब हो चुकी थी, जिसमें नाली और बारिश का पानी जमा हो रहा था। जिला प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि सिंह ने मौके पर ही सड़क की तत्काल मरम्मत के आदेश दिए, ताकि मानवी और उसके पड़ोसियों को जलभराव में से होकर न गुजरना पड़े।

इसके अलावा, अपने गहन निरीक्षण के दौरान लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी ने पाया कि यह इलाका अनियोजित विकास की समस्या से जूझ रहा है। जिलाधिकारी ने निवासियों को अव्यवस्थित 'प्लॉटिंग' के संभावित दुष्परिणामों के प्रति आगाह किया और उन्हें याद दिलाया कि वे आवासीय जमीन खरीदने से पहले जल निकासी, बिजली और सड़क के सही लेआउट की जांच-पड़ताल जरूर करें।

सर्विलांस सेल ने 50 लाख के 251 गुम मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए

देवरिया। जनपद के पुलिस की सर्विलांस सेल ने लगभग 50 लाख रुपये के 251 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को बुधवार को सौंप दिए। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के निर्देश पर सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से की गई। पुलिस अधीक्षकअभिजीत आर. शंकर ने बताया कि सर्विलांस सेल टीम ने गुम मोबाइल से संबंधित प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर लगातार काम करते हुए तकनीकी माध्यमों से ट्रैकिंग की। इसके परिणामस्वरूप कुल 251 आवेदकों के मोबाइल फोन बरामद किए गए। बुधवार को इन सभी मोबाइल फोन को नियमानुसार उनके स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्विलांस टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा 5,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया। इस दौरान एसपी ने उपस्थित लोगों से संवाद कर साइबर अपराधों के प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने बताया कि आजकल साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और ठग सोशल मीडिया, फर्जी कॉल, ईमेल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को निशाना बनाते हैं।

नागरिकों को सलाह दी गई कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें और किसी संदिग्ध लिंक या ऐप से दूर रहें। उन्होंने बताया कि साइबर ठगी की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया गया है, जिस पर तुरंत सूचना दी जा सकती है। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत डायल 112 पर देने की अपील की गई।

एलएसजी के खिलाफ बल्लेबाजी में लय वापस पाने की कोशिश करेगी आरसीबी

लखनऊ। पिछले मैच में बल्लेबाजों के नहीं चल पाने के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तालिका में शीर्ष पर जगह मनाने का मौका गंवाने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम गुरुवार को यहां सबसे निचले पायदान पर काबिज लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ बल्लेबाजी में अपनी लय फिर से हासिल करके प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आरसीबी फिलहाल अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, लेकिन उसके चार अन्य टीमों के समान 12 अंक हैं। उसकी टीम को अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स से चार विकेट से मिली हार को भूलकर जल्द से जल्द वापसी करनी होगी।

गुजरात के खिलाफ उस मैच में आरसीबी की बल्लेबाजी नाटकीय रूप से धराशायी हो गई थी। एक समय उसका स्कोर दो विकेट पर 79 रन था जो जल्द ही छह विकेट पर 96 रन हो गया और आखिर में उसकी टीम 155 रन पर आउट हो गई। आरसीबी के बल्लेबाज भले ही इस मैच में लड़खड़ा गए थे लेकिन वह दमदार वापसी करने में सक्षम हैं। उसके बल्लेबाजों ने अब तक आक्रामक खेल दिखाया है और लखनऊ के खिलाफ भी वह इसे जारी रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार फॉर्म दिखाते हुए 379 रन बनाए हैं, वहीं देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

नियमित सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट के उंगली में चोट के कारण बाहर होने से कोहली के साथ विस्फोटक शुरुआत देने की जिम्मेदारी जैकब बेथेल पर होगी। आरसीबी की टीम को एक सप्ताह के विश्राम का मौका मिला है और उसकी टीम इस मैच में अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में अधिक तरोताजा होकर उतरेगी। जहां तक एलएसजी का सवाल है तो उसका प्रदर्शन अभी तक निराशाजनक रहा है। वह पिछले छह मैचों में हार झेलने के कारण अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर है। इस बीच उसे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टाई रहे मैच में सुपर ओवर में भी हार का सामना करना पड़ा था। उसे पिछले मैच में मुंबई इंडियंस ने छह विकेट से करारी शिकस्त दी थी। एलएसजी का अभियान लगातार खराब प्रदर्शन, रणनीतिक अस्थिरता और मैचों का सकारात्मक अंत नहीं कर पाने के कारण कारण बिखर गया है। मिचेल मार्श, कप्तान ऋषभ पंत, एडन मार्क्रम और निकोलस पूरन जैसे प्रमुख बल्लेबाज अपने प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रख पाए हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी क्रम में बार-बार फेरबदल ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

पंत के सीमित ओवरों की क्रिकेट में प्रदर्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में एलएसजी के बल्लेबाजों के लिए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड की अगुवाई वाले आरसीबी के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना आसान नहीं होगा। भुवनेश्वर और हेजलवुड की जोड़ी बेहद प्रभावी साबित हुई है। उनके शानदार प्रदर्शन से आरसीबी ने 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स को मात्र 75 रन पर ढेर कर दिया था।

तेज गेंदबाज भुवनेश्वर विकेट लेने में किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं जबकि हेज़लवुड ने लगातार प्रभावशाली गेंदबाजी की है। क्रुणाल पंड्या ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए नौ विकेट लिए हैं। पिछले मैच में सुयश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। एलएसजी के लिए प्रिंस यादव और मोहसिन खान ने क्रमशः 13 और 10 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया है। मोहम्मद शमी ने सत्र की दमदार शुरुआत की थी, लेकिन पिछले कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और उन्होंने जमकर रन लुटाए हैं। आरसीबी ने पहले चरण में एलएसजी को पांच विकेट से हराया था और उसकी टीम काफी आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी।

इस प्रकार हैं दोनों टीम

- **रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु:** रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, जैकब बेथेल, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, अभिनंदन सिंह, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।
- **लखनऊ सुपर जायट्स:** ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), अब्दुल समद, अक्षत रघुवंशी, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, हिम्मत सिंह, जोश इंग्लिस, एडेन मार्क्रम, निकोलस पूरन , अर्शिन कुलकर्णी, जॉर्ज लिंडे, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, आकाश सिंह, अवेश खान, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, एनरिक नोर्किया, प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी, मणिमारन सिद्धार्थ, अर्जुन तेंदुलकर, नमन तिवारी, मयंक यादव।

मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड को हराकर 20 साल बाद चैंपियंस लीग फाइनल में बनाई जगह

लंदन। आर्सेनल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हराकर 20 साल बाद चैंपियंस लीग फाइनल में प्रवेश कर लिया। घरेलू मैदान एमिरेट्स स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल के दूसरे चरण में बुकायो साका के पहले हाफ के अंत में किए गए गोल ने टीम को जीत दिलाई।

पहले चरण में 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद आर्सेनल ने कुल मिलाकर 2-1 से मुकाबला अपने नाम किया। अब फाइनल में उसका सामना पेरिस सेंट-जर्मेन या बायर्न म्यूनिख से होगा, जो 30 मई को बुडापेस्ट में खेला जाएगा। आर्सेनल के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि टीम 2006 के बाद पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंची है। उस समय उसे बार्सिलोना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। क्लब अब तक इस प्रतिष्ठित खिताब को जीत नहीं सका है। मैच में आर्सेनल ने संयमित खेल दिखाया। शुरुआती मिनटों में एटलेटिको ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन आर्सेनल ने जल्द ही नियंत्रण हासिल कर लिया। 44वें मिनट में विक्टर ग्योकेरेस के शानदार मूव पर लिएंड्रो ट्रॉसार्ड ने शॉट लगाया, जिसे गोलकीपर ने रोक तो लिया, लेकिन रिबाउंड पर साका ने मौका भुनाते हुए गोल कर दिया। दूसरे हाफ में एटलेटिको ने वापसी की कोशिश की, लेकिन आर्सेनल की मजबूत डिफेंस और गोलकीपर ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। कोच मिकेल आर्टेटा के नेतृत्व में आर्सेनल इस सीजन शानदार फॉर्म में है और अब प्रीमियर लीग के साथ चैंपियंस लीग खिताब जीतने की दहलीज पर खड़ा है।

टीम अपने अंतिम तीन लीग मैच जीतकर खिताब भी अपने नाम कर सकती है। यह जीत आर्सेनल के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल के वर्षों में टीम को बड़े मुकाबलों में कमजोर मानसिकता के आरोप झेलने पड़े थे। अब यह टीम इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर है।

फीफा अध्यक्ष ने विश्व कप 2026 के टिकटों की ऊंची कीमतों का किया बचाव

बेवर्ली हिल्स। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने विश्व कप 2026 के टिकटों की बढ़ती कीमतों का बचाव करते हुए कहा कि वैश्विक फुटबॉल संस्था अमेरिकी कानूनों का लाभ उठाने के लिए बाध्य है, जो टिकटों को मूल कीमत से कई गुना अधिक पर पुनः बेचने की अनुमति देते हैं। विश्व कप टिकटों की कीमतों को लेकर फीफा की तीखी आलोचना हो रही है।

प्रशंसक संगठन 'फुटबॉल सपोर्टर्स यूरोप' (एफएसई) ने इस मूल्य निर्धारण को "अत्यधिक" और "विश्वासघात" करार दिया है। एफएसई ने मार्च में यूरोपीय आयोग में फीफा के खिलाफ "अत्यधिक टिकट कीमतों" को लेकर मुकदमा भी दायर किया था। फीफा के आधिकारिक पुनर्विक्रय मंच 'फीफा मार्केटप्लेस' पर पिछले सप्ताह 19 जुलाई को न्यूयॉर्क में होने वाले फाइनल मुकाबले के चार टिकटों की कीमत 20 लाख डॉलर से अधिक प्रति टिकट बताई गई थी। मिल्केन संस्थान ग्लोबल सम्मेलन में बोलते हुए इन्फैंटिनो ने कहा कि इतनी ऊंची कीमतें विश्व कप देखने की भारी मांग को दर्शाती हैं।

उन्होंने कहा, "अगर कुछ लोग फाइनल के टिकट 20 लाख डॉलर में बेचने के लिए डालते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि टिकट की असली कीमत इतनी है, और यह भी जरूरी नहीं कि कोई उन्हें खरीदे।" इन्फैंटिनो ने मजाकिया अंदाज में कहा, "अगर कोई 20 लाख डॉलर में टिकट खरीदता है, तो मैं खुद उसे हॉट डॉग और कोक दूंगा, ताकि उसका अनुभव शानदार रहे।"

प्रशंसक समूहों ने 2022 कतर विश्व कप और 2026 विश्व कप के टिकटों की कीमतों की तुलना करते हुए भारी अंतर पर सवाल उठाए हैं। 2022 में फाइनल का सबसे महंगा टिकट लगभग 1600 डॉलर था, जबकि 2026 में इसकी मूल कीमत करीब 11,000 डॉलर तक पहुंच गई है। इन्फैंटिनो ने इन कीमतों को उचित ठहराते हुए कहा कि यह बाजार की स्थिति के अनुरूप है। उन्होंने कहा, "हमें बाजार के हिसाब से चलना होता है। अमेरिका में टिकटों का पुनर्विक्रय भी अनुमति प्राप्त है, इसलिए अगर हम कीमत कम रखेंगे तो वे बाद में अधिक कीमत पर बिकेंगे।"

अहमदाबाद करेगा IPL फाइनल की मेजबानी, धर्मशाला और न्यू चंडीगढ़ में होंगे प्लेऑफ मैच

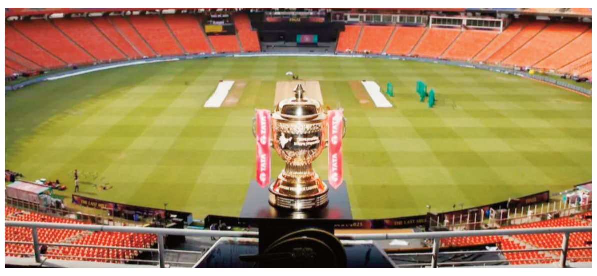

नई दिल्ली। बेंगलुरु के बजाय अहमदाबाद लगातार दूसरे सत्र में 31 मई को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के फाइनल की मेजबानी करेगा, जबकि क्वालीफायर एक धर्मशाला और दो अन्य प्लेऑफ मैच न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को यह घोषणा की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मौजूदा चैंपियन होने के कारण परंपरा के अनुसार फाइनल बेंगलुरु में खेला जाना था।

पिछले साल के अलावा अहमदाबाद ने इससे पहले 2022 और 2023 में आईपीएल फाइनल की मेजबानी की थी। बीसीसीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "आईपीएल फाइनल की मेजबानी के लिए मूल रूप से बेंगलुरु को चुना गया था। लेकिन स्थानीय संघ और अधिकारियों की कुछ ऐसी मांगों के कारण जो बीसीसीआई के स्थापित दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर थीं, आयोजन स्थल को स्थानांतरित कर दिया गया है।" बोर्ड ने हालांकि कर्नाटक की राजधानी में फाइनल आयोजित करने के लिए की जा रही मांगों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। बोर्ड ने यह भी कहा कि "संचालन और लॉजिस्टिकल से जुड़े मसलों के कारण इस वर्ष प्लेऑफ चरण के मैच तीन स्थानों पर खेले जाएंगे।"

बीसीसीआई ने कहा, "क्वालीफायर एक 26 मई को धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें भाग लेंगी। इस मैच के विजेता को फाइनल में सीधा प्रवेश मिलेगा।।" इसमें कहा गया है, "इसके बाद मुकाबले न्यू चंडीगढ़ के न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होंगे, जहां तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच 27 मई को एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। इसी स्टेडियम में 29 मई को क्वालीफायर दो भी खेला जाएगा।" धर्मशाला में पहली बार आईपीएल प्लेऑफ का कोई मैच खेला जाएगा। एलिमिनेटर में जीत दर्ज करने वाली टीम क्वालीफायर दो में क्वालीफायर एक में हारने वाली टीम का सामना करेगी।

इस मैच की विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी। बीसीसीआई ने कहा, "आईपीएल के मौजूदा सत्र का समापन 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ग्रैंड फाइनल के साथ होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है।" बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया कि अहमदाबाद स्टेडियम को उसकी अधिक दर्शकों की क्षमता के कारण प्राथमिकता दी गई क्योंकि फाइनल के लिए अधिक संख्या में दर्शकों के आने की संभावना है।

यह भी पता चला है कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की अपेक्षाकृत कम क्षमता को देखते हुए बोर्ड कर्नाटक सरकार के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें राज्य के विधायकों, एमएलसी और सांसदों के लिए इस सत्र में आईपीएल के तीन-तीन मुफ्त टिकटों का कोटा निर्धारित किया गया है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता लगभग 35,000 दर्शकों की है। पिछले साल आरसीबी के विजय समारोह के दौरान हुई भगदड़ में यहां 11 लोगों की जान चली गई थी।

इस प्रकार है प्लेऑफ़ का कार्यक्रम

- **क्वालीफायर एक:** 26 मई – एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला
- **एलिमिनेटर:** 27 मई – न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़
- **क्वालीफायर दो:** 29 मई – न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़
- **फाइनल:** 31 मई – नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद।

अमेरिका-ईरान वार्ता में प्रगति, तेल कीमतों में गिरावट से सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा

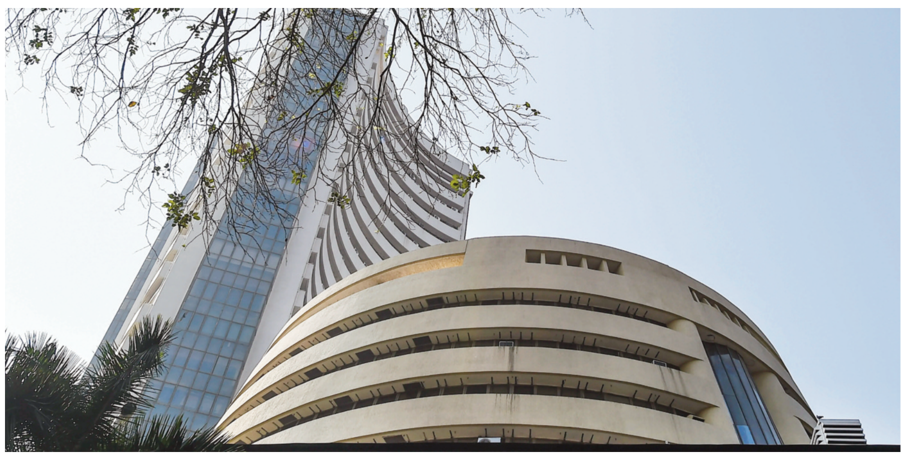

मुंबई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत में प्रगति के दावे के बाद बुधवार को स्थानीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंतिम घंटे में जोरदार लिवाली से बीएसई क 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 940.73 अंक यानी 1.22 प्रतिशत की छलांग के साथ 77,958.52 अंक पर पहुंच गया।

कारोबार के दौरान एक समय यह 1,004.99 अंक यानी 1.30 प्रतिशत की बढ़त के साथ 78,022.78 अंक पर पहुंच गया था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 298.15 अंक यानी 1.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,330.95 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख ने भी स्थानीय बाजार को समर्थन दिया। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से इंटरग्लोब एविएशन, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और इटर्नल के शेयर लाभ में रहे। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, पावर ग्रिड और एनटीपीसी के शेयरों में गिरावट आई। ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों को सुरक्षा देने के लिए 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' को स्थगित कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौते की दिशा में बातचीत में प्रगति हुई है। मंगलवार को 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, "ईरान के प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में काफी प्रगति हुई है।" होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने की वजह से फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सोमवार को 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' शुरू किया गया था। 'ट्रुथ सोशल' पर ट्रंप का बयान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के इस ऐलान के कुछ घंटों बाद आया है कि 28 फरवरी को शुरू किया गया ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' खत्म हो गया है और इसके मकसद पूरे हो गए हैं।

इस बीच, वैश्विक स्तर पर ब्रेंट कच्चा तेल आठ प्रतिशत टूटकर 101.1 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। लाइवलॉन्ग वेल्थ के शोध विश्लेषक और संस्थापक हरिप्रसाद के ने कहा, "यह काफी हद तक वैश्विक कारकों की वजह से था। अमेरिका-ईरान शांति समझौते को लेकर नई उम्मीद की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई है, जिससे भारत जैसी आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था को काफी राहत मिली है। अन्य एशियाई बाजारों में, द. कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ बंद हुए। कॉस्पी में छह प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया। दोपहर के कारोबार में यूरोप के बाजार बढ़त में थे।

अमेरिकी बाजार मंगलवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 3,621.58 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। सेंसेक्स मंगलवार को 251.61 अंक यानी 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,017.79 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 86.50 अंक यानी 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,032.80 अंक पर रहा था।

सेबी ने 'महत्वपूर्ण सूचकांक' के निर्धारण के लिए पेश की रूपरेखा

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने महत्वपूर्ण सूचकांक के निर्धारण के मामले में मंगलवार को एक नई रूपरेखा पेश की। इसके तहत किसी भी सूचकांक को उस समय 'महत्वपूर्ण सूचकांक' माना जाएगा, जब उसे ट्रैक करने वाली म्यूचुअल फंड योजनाओं का दैनिक औसत संयुक्त प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति (एयूएम) पिछले छह महीनों में लगातार 20,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा हो। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि इस कदम का उद्देश्य सूचकांक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है।

परिपत्र के मुताबिक, सूचकांक वर्गीकरण की यह सीमा प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली छमाही आधार पर आंकी जाएगी। नियामक ने स्पष्ट किया कि एक बार किसी सूचकांक को 'महत्वपूर्ण' श्रेणी में शामिल कर दिया गया तो वह इसमें बना रहेगा, जब तक कि उसका एयूएम लगातार तीन वर्षों तक निर्धारित सीमा से नीचे नहीं चला जाता। सेबी ने कहा कि सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर आधारित सूचकांक को तब 'महत्वपूर्ण सूचकांक' माना जाएगा जब वह म्यूचुअल फंड योजनाओं में छह महीने की अवधि के दौरान तय एयूएम मानदंड को पूरा करता है। यह कदम सेबी (सूचकांक प्रदाता) विनियम, 2024 के लागू होने के बाद आया है, जो ऐसे सूचकांक प्रदाताओं पर लागू होते हैं जो महत्वपूर्ण सूचकांक का प्रबंधन करते हैं।

सेबी ने ऐसे सूचकांकों की प्रारंभिक सूची भी जारी की है, जिसमें प्रमुख मानक सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 के साथ निफ्टी 500 और बीएसई 500 जैसे व्यापक सूचकांक शामिल हैं। इसके अलावा एनएसई इंडिसेस लिमिटेड, बीएसई इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और क्रिसिल के सेक्टोरल, डेट और हाइब्रिड इंडेक्स भी सूची में शामिल हैं। नए प्रावधान के तहत इन महत्वपूर्ण सूचकांकों के प्रदाताओं को छह महीने के भीतर सेबी में पंजीकरण कराना होगा।

रुपया 61 पैसे चढ़कर 94.57 प्रति डॉलर पर

मुंबई। रुपया बुधवार को 61 पैसे चढ़कर 94.57 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ संभावित समझौते के संकेत देने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत टूटकर 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचने से रुपया मजबूत हुआ है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि रुपये पर पड़ रहे भारी दबाव को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मुद्रा को समर्थन देने के लिए सक्रिय रूप से एक 'अप्रत्यक्ष' रणनीति भी अपना रहा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 पर खुला।

कारोबार के दौरान टूटकर 95.18 प्रति डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गया। अंततः 94.57 (अस्थायी) पर बंद रहा जो पिछले बंद भाव से 61 पैसे की बढ़त है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.18 पर बंद हुआ था। सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के प्रबंध निदेशक अमित पबारी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का सीधे उपयोग किए बिना मुद्रा को समर्थन देने के तरीकों की तलाश कर रहा है। पबारी ने कहा कि जिन विचारों पर चर्चा हो रही है उनमें से एक यह है कि सरकारी बैंकों को विदेशी मुद्रा बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिससे प्रणाली में डॉलर का नया प्रवाह लाने में मदद मिल सकती है। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 97.79 पर रहा। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स 940.73 अंक चढ़कर 77,958.52 अंक जबकि निफ्टी 298.15 अंक की बढ़त के साथ 24,330.95 अंक पर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 8.25 प्रतिशत गिरावट के साथ 100.81 डॉलर प्रति बैरल रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने 3,621.58 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

उत्तर प्रदेश रेरा ने कानूनी वारिसों के लिए फ्लैट हस्तांतरण शुल्क एक हजार रुपये तय किया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (उप्र रेरा) ने एक अहम फैसले में मूल आवंटनकर्ता की मृत्यु होने पर उसके कानूनी वारिसों को फ्लैट हस्तांतरित करने के लिए अधिकतम शुल्क एक हजार रुपये तय किया है। उप्र रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बुधवार को बताया कि अब विकासकर्ता या प्रवर्तक को मृतक आवंटी के जीवनसाथी, बेटे या बेटी को एक हजार रुपये के मामूली शुल्क लेकर फ्लैट हस्तांतरित करना होगा।

भूसरेड्डी ने यूपी रेरा के 10 साल पूरे होने पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्राधिकरण को कई शिकायतें मिली थीं जिनमें बिल्डर कथित तौर पर ऐसे हस्तांतरण के लिए मनमाना शुल्क वसूल रहे थे और कभी-कभी यह धनराशि लाखों रुपये तक पहुंच जाती थी। भूसरेड्डी ने कहा, "कुछ मामलों में शुल्क 200 रुपये से लेकर एक हजार रुपये प्रति वर्ग फुट तक होती थी, जिससे कुल रकम 25-30 लाख रुपये तक पहुंच जाती थी।

यह गलत है, खासकर तब जब आवंटनकर्ता पहले ही फ्लैट की पूरी कीमत चुका हो।" उन्होंने कहा कि इन शिकायतों के बाद प्रशासनिक और मानक शुल्क से सम्बन्धित नियम 47 को संशोधित किया गया है ताकि उत्तराधिकार या आवंटन हस्तांतरण के मामलों में प्रवर्तकों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क को नियंत्रित किया जा सके। भूसरेड्डी ने बताया कि संशोधित प्रावधानों के तहत खून के रिश्तों में आने वाले कानूनी वारिसों को फ्लैट हस्तांतरण करने पर अधिकतम एक हजार रुपये का प्रसंस्करण शुल्क लगेगा। उन्होंने बताया कि कानूनी वारिस को मूल आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और अन्य कानूनी वारिसों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। भूसरेड्डी ने कहा कि परिवार के बाहर के लोगों को फ्लैट हस्तांतरित करने पर अधिकतम 25 हजार रुपये शुल्क लिया जा सकता है लेकिन ऐसे मामलों में कोई नई बिक्री विलेख या पट्टा समझौता नहीं किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का मकसद बिल्डरों द्वारा की जाने वाली गलत हरकतों पर रोक लगाना और आवंटनकर्ता की मृत्यु के बाद संपत्ति के अधिकारों के हस्तांतरण के लिए एक पारदर्शी और मानक प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

वस्तुओं, सेवाओं का निर्यात बीते वित्त वर्ष बढ़कर 863.11 अरब डॉलर पर

नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद देश का वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात बीते वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 4.6% बढ़कर 863.11 अरब डॉलर के अबतक के उच्चस्तर पर पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्रालय के जारी संशोधित आंकड़ों से यह जानकारी मिली। इससे पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 825.26 अरब डॉलर रहा था। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वित्त वर्ष में वस्तुओं का निर्यात 0.93 % बढ़कर 441.78 अरब डॉलर रहा, जो 2024-25 में 437.70 अरब डॉलर था। एक अधिकारी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं और वस्तुओं के व्यापार में चुनौतियों के बावजूद भारत के वस्तु निर्यात में बढ़ोतरी हुई और इसने कुल निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेवाओं के निर्यात क्षेत्र का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। यह 2024-25 के 387.55 अरब डॉलर की तुलना में 2025-26 में बढ़कर सर्वकालिक उच्चस्तर 421.32 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यानी सेवाओं का निर्यात 8.71% बढ़ा। अधिकारी ने बताया कि सेवाओं के निर्यात में यह तेज बढ़ोतरी सूचना प्रौद्योगिकी, कारोबारी समाधान और पेशेवर विशेषज्ञता जैसी सेवाओं की बढ़ती वैश्विक मांग को दर्शाती है।

तारा सुतारिया और आदित्य रॉय चर्चा में

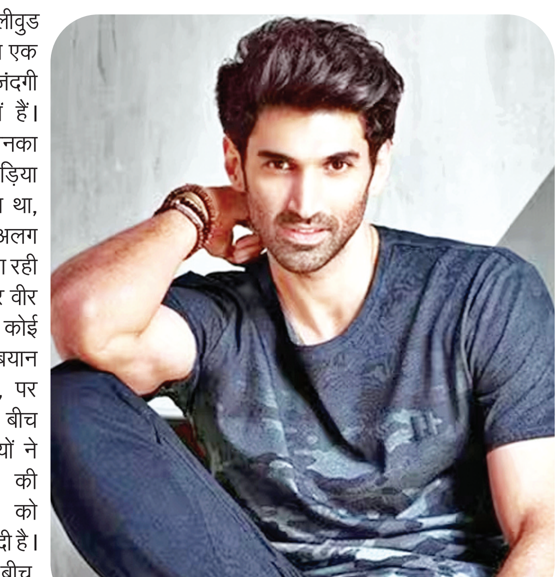

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री तारा सुतारिया एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले कुछ समय से उनका नाम अभिनेता वीर पहाड़िया के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब दोनों के अलग होने की खबरें सामने आ रही हैं। हालाँकि तारा और वीर की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर दोनों के बीच बढ़ती दूरियों ने ब्रेकअप की चर्चाओं को हवा दे दी है। इसी बीच, अब तारा सुतारिया का नाम अभिनेता आदित्य रॉय कपूर के साथ जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों को कई निजी मौकों पर एक साथ देखा गया है, जिसके बाद उनके रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर भी प्रशंसक दोनों की जोड़ी को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं और कई लोग उन्हें बॉलीवुड का नया कपल बता रहे हैं। सूत्रों की मानें तो दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है, जो अब एक खास रिश्ते में बदलती दिखाई दे रही है। हालाँकि, तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर ने अभी तक इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बावजूद इसके, दोनों की मुलाकातों और साथ बिताए गए समय ने प्रशंसकों की उत्सुकता बढ़ा दी है।

फिल्म 'राका' से फिर छाएंगे अल्लू अर्जुन, दिखेगा खास अंदाज

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'राका' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। 'पुष्पा' फ्रैंचाइजी की अपार सफलता के बाद अब दर्शकों को उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच फिल्म के शीर्षक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है कि 'राका' का सीधा संबंध पुष्पा की सफलता से जुड़ा हुआ है।रिपोर्ट्स के मुताबिक, निर्माताओं ने 'राका' नाम सोच-समझकर चुना है और इसे फिल्म में अल्लू अर्जुन के किरदार के नाम पर रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि 'पुष्पा' में अभिनेता ने अपने किरदार को जिस तरह से जीवंत किया, वह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान बन गया। इसी प्रभाव को दोहराने के लिए मेकर्स ने 'राका' को भी किरदार-केंद्रित फिल्म के रूप में पेश करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि 'राका' की पूरी कहानी मुख्य किरदार की ताकत और व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द बुनी गई है। ठीक वैसे ही जैसे पुष्पा में देखने को मिला था। इस फिल्म का निर्देशन एटली कर रहे हैं और इसमें दीपिका पादुकोण भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि 'राका' भी बॉक्स ऑफिस पर 'पुष्पा' जैसा ही जादू दोहराएगी।

वृंदावन में बिता रहीं जीवन अन्ना जयसिंघानी

मुंबई। टीवी इंडस्ट्री की अभिनेत्री अन्ना जयसिंघानी ने ग्लैमर की दुनिया छोड़कर अध्यात्म का रास्ता अपना लिया है। एकता कपूर के शो से पहचान बनाने वाली अन्ना ने अब अभिनय से दूरी बनाकर पूरी तरह कृष्ण भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया है। हाल ही में उन्होंने अपने आध्यात्मिक सफर और जीवन में आए बदलावों को लेकर खुलकर बात की। अन्ना जयसिंघानी ने अपने यूट्यूब चैनल 'मेरो वृंदावन' के जरिए बताया कि अब उन्हें वह दुनिया आकर्षित नहीं करती जहाँ भगवान का नाम और भक्ति न हो। उन्होंने कहा कि अभिनय और ग्लैमर की चमक के बीच भी उनके मन को सच्ची शांति नहीं मिल रही थी। इसी कारण उन्होंने सब कुछ छोड़कर वृंदावन में रहने का फैसला किया। अभिनेत्री ने बताया कि बचपन से ही उन्हें नृत्य, संगीत और अभिनय का शौक था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह मुंबई पहुँचीं और वर्ष 2011 में कोरियोग्राफर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया और धीरे-धीरे पहचान बनाई। अन्ना ने कहा कि मुंबई में रहते हुए वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ इस्कॉन मंदिर जाया करती थीं, और वहीं से उनके भीतर आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव बढ़ने लगा। उन्होंने धीरे-धीरे शराब और मांसाहार से दूरी बना ली और भगवान कृष्ण की भक्ति में मन लगाने लगीं।

भारत-सूरीनाम संबंध 'पारिवारिक' बंधन पर आधारित हैं : जयशंकर

परामारिबो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सूरीनाम को 'दूर का साझेदार' नहीं बल्कि 'परिवार' के रूप में देखता है। उन्होंने दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर यह टिप्पणी की। बुधवार को सूरीनाम की यात्रा से पहले 'टाइम्स ऑफ सूरीनाम' अखबार में लिखे लेख में जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंध अब 'मजबूत और बहुआयामी साझेदारी' में बदल गए हैं, जिसमें बुनियादी ढांचा, व्यापार, प्रशिक्षण और सांस्कृतिक संबंध शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि भारत और सूरीनाम ने उच्चस्तरीय यात्राओं के जरिए सहयोग को और मजबूत किया है। इसमें 2023 में सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी की भारत यात्रा और उसी वर्ष भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा शामिल है। जयशंकर ने बताया कि 'इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट' (रियायती दरों पर ऋण) के जरिए सूरीनाम में कई परियोजनाएं पूरी की

गई हैं, जिनमें परानाम औद्योगिक बंदरगाह शहर से राजधानी परामारिबो तक 161 किलो वॉट की विद्युत ट्रांसमिशन लाइन, जल पंपिंग स्टेशन, निर्माण उपकरण, बिजली ढांचे का उन्नयन और तीन चेतक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति व रखरखाव शामिल हैं। उन्होंने लिखा कि भारत ने पिछले वर्ष सूरीनाम को खाद्य सुरक्षा में मदद के लिए एक करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य के 425 मीट्रिक टन खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराए।

विदेश मंत्री ने कहा कि भारत समर्थित अनुदान परियोजनाओं में बाढ़ चेतावनी प्रणाली, एक स्टेडियम तथा शिक्षा, खेल और तकनीकी प्रशिक्षण से जुड़े सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं। जयशंकर ने यह भी बताया कि वह भारतीय अनुदान से स्थापित 'पैशन फ्रूट प्रोसेसिंग और पैकेजिंग इकाई' के उद्घाटन में शामिल होंगे। उन्होंने लिखा कि यह स्थानीय किसानों को सशक्त बनाएगा और मूल्यवर्धित उद्योग के जरिए सूरीनाम की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और सूरीनाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जैसे मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सूरीनाम, भारत समर्थित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और 'इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस' जैसी पहलों में भागीदार है। जयशंकर ने कहा कि भौगोलिक दूरी के बावजूद दोनों देश साझा इतिहास से जुड़े हुए हैं, जिसकी शुरुआत 1873 में 'लल्ला रूख' जहाज के जरिए भारतीयों के सूरीनाम पहुंचने से हुई थी। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल का समुदाय सूरीनाम के समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जिसने सरनामी हिंदुस्तानी भाषा, बैठक संगीत और दिवाली व फगवा जैसे त्योहारों की परंपरा को भी संजोए रखा है। उन्होंने लिखा कि सूरीनाम ने वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के प्रचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जयशंकर ने बताया कि 2003 में परामारिबो में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत, सूरीनाम को किसी दूर के साझेदार के रूप में नहीं, बल्कि अपने परिवार के रूप में देखता है।

हार्मुज से जहाजों को निकालने का अमेरिकी अभियान दो दिनों के भीतर रुका

नौसैनिक घेराबंदी जारी रहेगी : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोकने की घोषणा की। यह मिशन हार्मुज जलडमरूमध्य में फंसे जहाजों को निकालने के लिए था। ट्रंप ने पाकिस्तान और अन्य देशों से मिले अनुरोधों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया।

हालांकि, ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मुज जलडमरूमध्य में फंसे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोकने की घोषणा की है। लेकिन ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध पर और ईरान के खिलाफ चलाए गए अभियान में हमारी सेना को मिली ज़बरदस्त सफलता को देखते हुए—साथ ही इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईरान के प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में काफी

प्रगति हुई है—हमने आपसी सहमति से यह तय किया है कि, 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' (होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही) को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। हालांकि नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यह देखा जा सके कि क्या वह समझौता अंतिम रूप ले पाता है और उस पर हस्ताक्षर हो पाते हैं या नहीं।

ट्रंप ने रविवार को यह कहते हुए इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी कि दुनिया भर के देशों ने अपने जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। इसके बाद सोमवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह ऑपरेशन शुरू किया था। खास बात यह है कि अमेरिका इस ऑपरेशन के तहत सोमवार को दो और मंगलवार को सिर्फ एक जहाज सुरक्षित निकाल पाया था।

जबकि ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल टकराव शुरू होने से पहले हर दिन हार्मुज से औसतन सवा सौ जहाज गुजरते थे।अमेरिका की इस मुहिम से नाराज ईरान ने चेतावनी दी थी कि उसकी इजाजत के बिना कोई जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर सकता। इसके बाद ईरान ने हार्मुज में साऊथ कोरिया के एक जहाज पर हमला किया। साथ ही यूएई पर मिसाइल हमले किए।

ईरान में एक 'शॉपिंग सेंटर' में आग लगने से आठ लोगों की मौत, कई लोग घायल

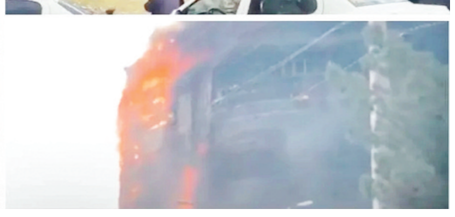

तेहरान। ईरान की राजधानी के समीप एक 'शॉपिंग सेंटर' में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। आपात सेवा विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी।

ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल 'आईआरआईबी' ने बताया कि तेहरान प्रांत के अंदिशेह कस्बे में स्थित 'अर्घावन शॉपिंग सेंटर' में मंगलवार को आग लग गई और आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। टेलीविजन पर दिखाए गए फुटेज में दमकलकर्मी आग की लपटों को बुझाने के काम में लगे दिखाई दिए, वहीं बहुमंजिला इमारत से काले धुएं का गुबार उठता भी नज़र आ रहा है। फिलहाल इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि आगजनी की घटना ईरान-अमेरिका युद्ध से जुड़ी हुई थी। यहां अमेरिका के साथ लगभग तीन सप्ताह से एक अस्थिर युद्धविराम कायम है।

यूक्रेन के एकतरफा युद्धविराम को रूस ने ठुकराया, रातभर ड्रोन हमले किए

कीव। रूस ने यूक्रेन द्वारा घोषित एकतरफा युद्धविराम की अनदेखी करते हुए रातभर दर्जनों ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यूक्रेन द्वारा आधी रात से लागू किए गए युद्धविराम के बावजूद हमले जारी रहे।

वहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन ने स्वयं अपने युद्धविराम का पालन नहीं किया और उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने मंगलवार शाम से बुधवार सुबह तक रूसी क्षेत्रों, अवैध रूप से कब्जाए गए क्रीमिया प्रायद्वीप और काला सागर के ऊपर 53 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। रूस द्वारा नियुक्त गवर्नर सर्गेई अक्स्योनोव के अनुसार, क्रीमिया के झानकोय शहर पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में पांच लोगों की मौत हो गई। उन्होंने आधी रात के बाद हताहतों की जानकारी दी, जबकि हमले के बारे में उन्होंने करीब 90 मिनट पहले पोस्ट किया था। मॉस्को की ओर से यूक्रेन

के युद्धविराम का पालन करने का कोई संकेत नहीं मिला था और युद्धविराम की उम्मीद भी कम ही थी, क्योंकि रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद यह युद्ध का पांचवा साल है।

पिछले एक वर्ष में अमेरिका के नेतृत्व में हुए कूटनीतिक प्रयास भी विफल रहे हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर क्लीमेंको के अनुसार, मंगलवार को रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों की मौत हुई और 120 अन्य घायल हुए, जिनमें सभी नागरिक थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस युद्ध में अब तक 15,000 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है। दोनों पक्ष लंबी दूरी के हमलों को जारी रखे हुए हैं। लगभग 1,250 किलोमीटर लंबी अग्रिम पंक्ति पर रूस की बड़ी सेना यूक्रेन की ड्रोन-आधारित रक्षा के खिलाफ धीमी और महंगी लड़ाई में उलझी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एकतरफा युद्धविराम की घोषणा उस समय की थी, जब रूस ने इस सप्ताह के अंत में द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की हार की 81वीं वर्षगांठ के अवसर पर दो दिनों के युद्धविराम का प्रस्ताव दिया था। जेलेंस्की ने कहा था कि युद्धविराम के किसी भी उल्लंघन पर सैन्य जवाब दिया जाएगा।

यूरोपीय अधिकारियों ने यूक्रेन के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे शांति समझौते के लिए उसकी तत्परता का संकेत बताया। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि रूसी बलों ने रातभर में 108 ड्रोन और तीन मिसाइलें दागीं और हमले बुधवार सुबह तक जारी रहे। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि मॉस्को ने एक बार फिर संघर्ष समाप्त करने की यथार्थवादी और न्यायसंगत अपील को नजरअंदाज किया, जिसे अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त था। रूस द्वारा शुक्रवार और शनिवार को युद्धविराम का प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब वह विभिन्न अवसरों, विशेषकर हाल ही में ईस्टर जैसे त्योहारों पर अल्पकालिक युद्धविराम घोषित करता रहा है।

हालांकि, दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास के कारण ऐसे युद्धविराम का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है। सिबिहा ने कहा कि रूस की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि नौ मई के आसपास युद्धविराम की उसकी अपील ईमानदार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को केवल सैन्य परेड की चिंता है, मानव जीवन की नहीं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मॉस्को पर दबाव बढ़ाने की अपील करते हुए नए प्रतिबंध, कूटनीतिक अलगाव, युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही तय करने और यूक्रेन को सैन्य व नागरिक सहायता बढ़ाने की मांग की।